●वर्ष-5
●अंक-225
रायपुर, शुक्रवार 08 मई 2026
●पृष्ठ-8
●मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› बिजली बिल भुगतान समाधान...

नीति की सफलता के लिए जनता का साथ अनिवार्य: भागवत

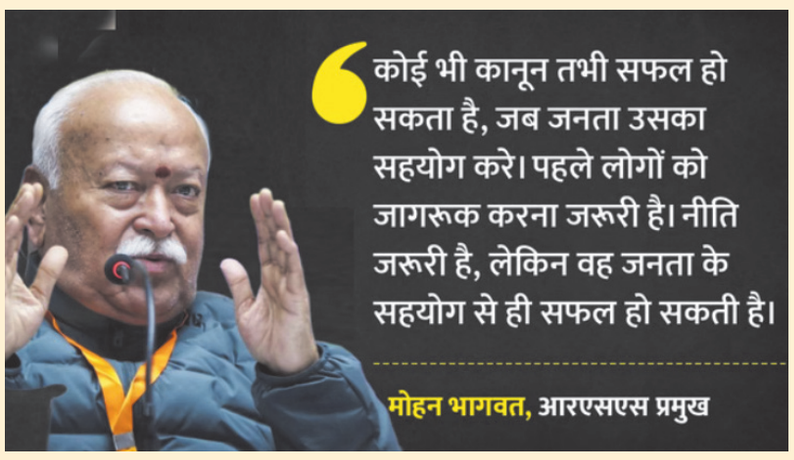

मैसूर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए जनता का सहयोग और दीर्घकालिक विचार जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जाति आधारित राजनीति तभी खत्म होगी, जब समाज खुद जातिगत पहचान से ऊपर उठेगा।

आरएसएस प्रमुख ने मैसूरु में राष्ट्रीय विकास में सामाजिक समरसता की भूमिका% विषय पर व्याख्यान के बाद आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहा कि समाज में धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द होना चाहिए। उन्होंने लोगों से नारेबाजी के बजाय बराबरी का व्यवहार करने की अपील की।भागवत ने कहा, समाज जाति को याद रखता है, इसलिए राजनेता उसका फायदा उठाते हैं। उनका उद्देश्य वोट हासिल करना होता है। जब काम के आधार पर वोट नहीं मिलते, तो वे जाति के आधार पर वोट लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक और यूसीसी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरएसएस सरकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक संगठन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी कानून तभी सफल हो सकता है, जब जनता उसका सहयोग करे।उन्होंने कहा, पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है। नीति जरूरी है, लेकिन वह जनता के सहयोग से ही सफल हो सकती है। आपातकाल के दौरान अपनाए गए जनसंख्या नियंत्रण उपायों का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि सख्ती से लागू की गई नीतियों के कारण लोगों में नाराजगी और राजनीतिक विरोध पैदा हुआ था।

कार्यक्रम में बताया क्या है आरएसएस

उन्होंने कहा कि समाज जाति को याद रखता है, इसलिए राजनेता उसका लाभ उठाते हैं। उनका उद्देश्य वोट प्राप्त करना होता है। यदि उन्हें काम के आधार पर वोट नहीं मिलते, तो वे जाति के आधार पर वोट हासिल करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक और समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि आरएसएस सरकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक संगठन है।

आपातकाल का किया जिक्र

उन्होंने कहा कि पहले लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। नीति आवश्यक है, लेकिन नीति तभी सफल होगी जब जनता का सहयोग मिलेगा। आपातकाल के दौरान अपनाए गए जनसंख्या नियंत्रण उपायों का उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा कि आक्रामक तरीके से लागू की गई नीतियों के कारण जनता में असंतोष पैदा हुआ था।

ममता बनर्जी नहीं रहीं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा संवैधानिक निर्णय सामने आया है। राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। लोक भवन, पश्चिम बंगाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किया गया है।

7 मई 2026 से लागू हुआ आदेश

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा को 7 मई 2026 से प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया है। यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया है। लोक भवन की अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(बी) के तहत राज्यपाल को प्राप्त अधिकारों के आधार पर लिया गया है।

विधायक दल की अहम बैठक

इसी पश्चिम बंगाल में शनिवार को शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इससे पहले, केंद्रीय पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में शुक्रवार शाम चार बजे विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा।

टैगोर की जयंती से संदेश देने की कोशिश

तृणमूल कांग्रेस के बंगाली अस्मिता के मुद्दे की प्रभावी रूप से हवा निकालने के लिए भाजपा ने शपथ ग्रहण के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती को चुना है। इस दिन 25वां वैशाख है, जो बंगाली कैलेंडर के मुताबिक टैगोर जयंती है। हालांकि अंग्रेजी भाजपा कार्यालय में सीएम पद कैलेंडर के हिसाब से उनकी के दावेदार शुभेदु अधिकारी जयंती 7 मई को होती है

बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे?

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा ने राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 207 सीटों पर कब्जा जमाया है। इस जीत के साथ ही भाजपा ने दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है और बंगाल में टीएमसी के 15 साल के राज को खत्म कर दिया है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी की पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इस हार के बाद ममता बनर्जी ने अब अपनी पूरी ताकत इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगाने का संकल्प लिया है।

बिहार कैबिनेट विस्तार

10 पुराने चेहरों पर फिर जताया भरोसा, एक मुस्लिम मंत्री और 2 नामों ने चौंकाया

पटना। बिहार में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जनता दल यूनाइटेडने अपनी पुरानी टीम पर भरोसा बरकरार रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 पूर्व मंत्रियों को फिर से कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि तीन नए चेहरों को पहली बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रियों में निशांत कुमार, शैलेश कुमार (बुलो मंडल) और श्वेता गुप्ता के नाम शामिल हैं।

10 दिग्गज जो फिर बने मंत्री

श्रवण कुमार: नालंदा से लगातार 8 बार के विधायक और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद। वे ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं।

लेशी सिंह: पूर्णिया के धमदाहा से विधायक लेशी सिंह पूर्व में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रह चुकी हैं। वे नीतीश सरकार का महिला चेहरा हैं।

दामोदर रावत: झाझा से विधायक और 5 बार से अधिक चुनाव जीत चुके रावत पूर्व में भी नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं।

अशोक चौधरी: मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी नीतीश कुमार के रणनीतिकारों में गिने जाते हैं।

भगवान सिंह कुशवाहा: जगदीशपुर से विधायक और कुशवाहा समाज के बड़े नेता। स

मदन सहनी- दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक सहनी अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रत्नेश सदा: सहरसा के सोनबरसा से चार बार के विधायक।

शीला कुमारी (मंडल)- मधुबनी के फुलपरास से विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री।

सुनील कुमार: रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और भोरे से विधायक।

जमा खां: कैबिनेट का इकलौता मुस्लिम चेहरा।

राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण दें तो विधानसभा में बहुमत साबित करुंगा: विजय

■ राज्यपाल ने फिर खाली हाथ लौटाया

चेन्नई। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय ने गुरुवार सुबह आर वी अर्लेकर से मुलाकात की। यह मुलाकात राजभवन को यह समझाने का एक नया प्रयास था कि तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने के लिए तमिलगा वेट्री कज़गम को जरुरी समर्थन हासिल है। यह मुलाकात विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच हुई है, जिसमें पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है तो वे विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि यदि राज्यपाल उनके नए दावे पर विचार करने से इनकार करते हैं तो पार्टी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। बुधवार को विजय का सीएम पद पर दावा पेश करने का पहला प्रयास विफल रहा, क्योंकि राज्यपाल ने गठबंधन की संख्या बल पर आपत्ति जताई थी।इससे पहले टीवीके प्रमुख विजय के बुधवार दोपहर को सीएम पद की शपथ लेने की उम्मीद थी।

लेकिन बहुमत के समर्थन को लेकर सवाल अनसुलझे रहने के कारण शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल ने सरकार बनाने का निमंत्रण जारी करने से पहले विजय से विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण देने पर जोर दिया।

प्रमुख समाचार

मोदी ने एक्स की डिस्प्ले तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर की

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर अपने सोशल मीडिया एक्स की डिस्प्ले तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर कर ली है और सैनिकों के पराक्रम और देशभक्ति की सराहना की है। श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बहादुरी को नमन करते हुए एक्स पर लिखा,

ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। उन्होंने इस मौके पर महाभारत का एक श्लोक को एक्स पर पोस्ट किया, उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत। यस्यां भवन्ति सेनायां ध्रुवं तस्यां जयं वदेत। इस श्लोक का अर्थ है हे भरतवंशी (युधिष्ठिर)! जिस सेना के सैनिक और वाहन (घोड़े, हाथी, रथ आदि) उत्साही और उच्च मनोबल वाले होते हैं, उस सेना की विजय निश्चित समझनी चाहिए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारतीय सेना ने सात मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।

10 मई को केरल सीएम का ऐलान कर सकते हैं खड़गे

नई दिल्ली। केरल में कांग्रेस की जीत के बाद सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 10 मई रविवार को केरल के सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। विधायकों की बैठक में एक-लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ। केरल के सीएम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है।

कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने गुरुवार को कहा कि केरल में चल रही कांग्रेस विधायक दल की प्रक्रिया पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को दर्शाती है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी पर भी कोई फ़ैसला थोपा नहीं जा रहा है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधायक दल की बैठक और विधायकों के साथ विचार-विमर्श के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों और सीनियर नेताओं से मिली राय पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद पार्टी आलाकमान सीएम पद के उम्मीदवार पर अंतिम फ़ैसला लेगा। सूत्रों के मुताबिक अगर केरल में वी डी सतीशन को सीएम पद का चेहरा नहीं चुना जाता है, तो वे कड़ा रुख अपना सकते हैं।

टीएमसी के जंगलराज का परिणाम है चंद्रनाथ की हत्या : शुभेंदु

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इस घटना को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे तृणमूल कांग्रेस के महा जंगल राज का परिणाम बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव

नतीजों के बाद राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारी ने बशीरहाट में एक कार्यकर्ता को गोली मारे जाने और बारानगर में एक अन्य पर चाकू से हुए हमले का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा की है। हालांकि, उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक ने उन्हें उचित जांच का आश्वासन दिया है और पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

बंगाल में नहीं थम रही हिंसा हावड़ा में झड़प, एक घायल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के कई इलाकों में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। गुरुवार को हावड़ा के शिवपुर स्थित चौराबस्ती इलाके में कथित तौर पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है।नतीजे आने के बाद से ही राज्य के अलग-अलग हिस्सों में खूनी खेल शुरू हो गया है। चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद शांति बहाल होने के बजाय हिंसा और राजनीतिक टकराव की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर 24 परगना जिले का पानीहाटी इलाका उस वक्त दहल उठा जब वहां भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर बम फेंके गए। एक तरफ जहां लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंसा की इन घटनाओं ने आम आदमी के मन में डर पैदा कर दिया है। यह हिंसा केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि बसीरहाट, बरानगर और हावड़ा जैसे क्षेत्रों से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं।उत्तर 24 परगना के पानीहाटी इलाके में गुरुवार की सुबह जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया।

'हर धार्मिक प्रथा को चुनौती गलत', : सुप्रीम कोर्ट क

नईदिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामलों को अदालत में चुनौती देने लगेंगे, तो इससे धर्म और समाज पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सैकड़ों याचिकाएं अलग-अलग रीति-रिवाजों पर आने लगेंगी और हर रिवाज पर सवाल उठने लगेंगे। इससे धर्म और सभ्यता दोनों को नुकसान हो सकता है। यह टिप्पणी नौ जजों की

संविधान पीठ ने की, जो अलग-अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला और दाऊदी बोहरा समुदाय का केस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ी 40 साल पुरानी जनहित याचिका (क्षुरु) की वैधता पर सवाल उठाए थे। दाऊदी बोहरा समुदाय की केंद्रीय संस्था ने 1986 में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें 1962 के उस फैसले को निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसमें बंबई बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1949 को रद कर दिया गया था।

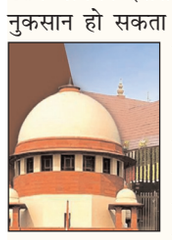

मुखर्जी-गोलवलकर की एक मुलाकात ने बदल दी दिशा

एन अर्जुन

उत्तर कोलकाता की संकरी गलियों और पुराने मकानों के बीच स्थित 26 नंबर विधानसरिणी एक साधारण सा पता जरूर लगता है, लेकिन यह वही जगह है, जहां करीब 75 साल पहले भारतीय राजनीति का एक ऐसा विचार जन्मा, जिसने आगे चलकर देश की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित यह भवन आज प्रज्ञा मंदिर के नाम से जाना जाता है।

यह अपने में इतिहास की कई परतों को समेटे हुए है। बाहर से देखने पर यह इमारत बिल्कुल सामान्य लगती है, पर जैसे ही कोई इसके छोटे से गेट से अंदर प्रवेश करता है और लकड़ी की पुरानी, घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, एक अलग ही दुनिया सामने खुलती है। दीवारों पर देशभक्ति और विचारधारा से जुड़े चित्र, ऊपर की मंजिल पर पुस्तकालय और शांत वातावरण, यह सब उस दौर की याद दिलाते हैं, जब यहां बैठकर बड़े फैसले लिए जाते थे।

एक मुलाकात, जिसने बदली दिशा

इतिहास के पन्नों को याद करते हुए बिप्लव राय, आरएसएस के प्रांत प्रचार प्रमुख, बताते हैं, 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली बार यहां आए और एमएस गोलवलकर से मुलाकात की। नेहरू सरकार से मतभेद, खासकर कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर इस्तीफा देने के बाद मुखर्जी एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच की तलाश में थे। इस मुलाकात के दौरान गोलवलकर ने दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को उनके साथ जोड़ा। यहीं, इसी भवन के एक कमरे में एक विचार ने संगठन का रूप लिया और 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई, जिसका चुनाव चिह्न दीपक तय किया गया।

1940 में माधव स्मृति के रूप में स्थापित यह स्थान पूर्व भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। यहां से 40 से अधिक सामाजिक और राष्ट्रीय प्रकल्पों को मूर्त रूप दिया गया। नोआखाली दंगों के दौरान पीड़ितों को यहीं आश्रय मिला। यही वह जगह है, जहां बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति की दिशा तय करने वाली रणनीतियां तैयार कीं और दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया। दूसरी मंजिल पर स्थित पुस्तकालय आज भी उसी रूप में मौजूद है।

जनसंघ से भाजपा तक

1952 के पहले आम चुनाव में जनसंघ ने तीन सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद पार्टी ने धीरे-धीरे अपने आधार को मजबूत किया और बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के नेतृत्व में विस्तार किया।

1975 में आपातकाल और उसके बाद 1977 में जनता पार्टी का गठन भारतीय राजनीति का अहम मोड़ बना। हालांकि 1980 में मतभेदों के चलते जनता पार्टी टूट गई और उसी से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिसका चुनाव चिह्न कमल बना। दीपक से कमल तक का यह 75 साल का सफर केवल एक राजनीतिक दल का विकास नहीं, बल्कि एक विचारधारा के विस्तार की कहानी है, जिसकी शुरुआत 26 नंबर विधानसरिणी से हुई थी।

अब नहीं सुनना पड़ेगा ताना

भाजपा समर्थक रंजना कहती हैं कि पार्टी पिछले कई दशकों से बंगाल में सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही थी। उनके अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ता आधार वाली इस पार्टी के लिए यह एक लंबे समय से देखा गया सपना था कि जिस बंगाल में जनसंघ की नींव पड़ी, वहां वह कभी सरकार नहीं बना सकी। रंजना कहती हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में वह सपना अब साकार हो गया है। अब उन आलोचनाओं का भी जवाब मिल गया है, जिनमें कहा जाता था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल से जुड़े होने के बावजूद पार्टी राज्य में कभी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। वे कहती हैं कि अब स्थिति बदल चुकी है और पार्टी कार्यकर्ताओं को वह पुराना ताना नहीं सुनना पड़ेगा, जिसमें कहा जाता था, विचार तो बड़ा है, लेकिन बंगाल में सरकार कभी नहीं बन पाई।

सुरक्षा बलों की सर्चिंग में खुल रहे माओवादियों के गुप्त राज

■ बस्तर में 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी छिपे होने का अंदेशा

जगदलपुर। बस्तर में माओवादी नेटवर्क के कमजोर पड़ने के साथ अब उनके आर्थिक ढांचे की परतें खुलने लगी है। सुरक्षा बलों की लगातार सर्चिंग में ऐसे डंप सामने आ रहे हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संगठन सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक जाल पर भी टिका था। बीते तीन महीनों में जवानों ने करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए नगद और 8 किलो सोना बरामद किया है, जो इस छिपे खजाने की एक झलक भर है। आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक, यह बरामदगी अंदरूनी इलाकों में छिपाकर रखे गए डंप से हुई है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है।

जानकार बताते हैं कि नोटबंदी के बाद माओवादियों ने रणनीति बदली और नगद की जगह सोने में निवेश करना शुरू किया, ताकि जोखिम कम रहे। बरामद 8 किलो सोने की कीमत ही करीब 13 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे संगठन की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह पैसा तेंदूपत्ता संग्राहकों, ठेकेदारों और विकास कार्यों में लगे लोगों से लेवी के रूप में वसूला जाता था, जो साल दर साल करोड़ों में पहुंचता था। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी मानते हैं कि अब तक मिली रकम सिर्फ सतह है, असल में बस्तर में ही माओवादियों की छिपी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यानी जैसे-जैसे माओवादी नेटवर्क खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे उनका आर्थिक साम्राज्य भी उजागर हो रहा है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि जंगलों में छिपे ऐसे कई डंप अब भी सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं।

फिलहाल बस्तर में जारी सर्च ऑपरेशन सिर्फ हथियारों की तलाश नहीं, बल्कि माओवादियों की उस आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश भी है, जिस पर उनका पूरा नेटवर्क खड़ा था।

बेटे की मौत के सदमे में टूटा पिता, दुर्गा मंदिर में काट ली अपनी जीभ

रायगढ़। दुर्गा मंदिर घरघोड़ा से सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने पूरे नगर को झकझोर कर रख दिया। एफसीआई गोदाम के पास रहने वाले सनत कुमार खांडे ने गहरे मानसिक सदमे में मंदिर परिसर के बाहर अपनी जीभ काट ली। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में हड़कंप की स्थिति बन गई। घटन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

बताया जा रहा है कि सनत कुमार खांडे के 8 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार खांडे की कल शाम तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। बेटे की असमय मौत से पिता पूरी तरह टूट चुका था। परिजनों और आसपास के लोगों के अनुसार वह रातभर बेहद विचलित और मानसिक तनाव में था। इसी सदमे के बीच आज सुबह लगभग 3 बजे वह प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर पहुंचा और कथित रूप से आस्था व दर्द के आवेग में अपनी जीभ काट ली। घटना के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने से सतन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने तत्काल उसे संभालने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौके पर एकजुट हुए।

बस्तर में बैंकिंग नेटवर्क, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण

■ बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद वहां के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर सरकार फोकस कर रही है.

बस्तर। बस्तर संभाग में लगातार बैंक की नई शाखाएं खुल रहीं हैं। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के तर्रेम में भी बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखा खुली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। पिछले ढाई साल में बस्तर संभाग में खुलने वाली यह 31वीं नई बैंक शाखा है। ग्रामीणों ने तर्रेम में बैंक शाखा खुलने पर खुशी जताई और इसे अपने लिए बड़ी सुविधा बताया।

ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से न केवल बैंकिंग सेवाएं सुलभ होंगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा मिलेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तर्रेम में बैंक शाखा खुलने से स्थानीय लोगों को अब बैंकिंग कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने क्षेत्र में ही सभी आवश्यक सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी.इससे पहले भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दंतेवाड़ा-सुकमा जिले के सीमावर्ती जगरगुंडा क्षेत्र में बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर अब बदलाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं।

यह नक्सल मुक्त बस्तर की दिशा में बढ़ते कदमों के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग में बैंकिंग सुविधाओं के लगातार विस्तार को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं से आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा।

8-15 साल के मासूमों को बंधक बना कराते थे मजदूरी, 8 आरोपी गिरफ्तार

■ 6 महीने तक बंधक बने रहे बैगा बच्चे

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के जंगल व पहाड़ी इलाकों से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के 13 नाबालिग बच्चों को उनके माता-पिता को पैसों का लालच देकर गांवों से ले जाया गया और फिर महीनों तक उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया गया। बच्चों की उम्र महज 8 से 15 साल के बीच है। इस मामले को लेकर आज गुरुवार को खुलासा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मासूमों से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार मवेशी चराने, देखभाल करने व अन्य कठिन काम कराए जाते थे। इसके बदले बच्चों को एक रुपया तक नहीं मिलता था। उनके माता-पिता को सिर्फ एक से दो हजार रुपए महीने देकर बच्चों को अपने कब्जे में रखा गया था। एसपी धर्मेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि ग्राम थूहापानी और आसपास के इलाकों से बैगा जनजाति के कई बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है और उनसे जबरन मजदूरी कराई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे मानव तस्करी और बाल शोषण का गंभीर मामला मानते हुए विशेष टीम गठित की। इसके बाद पुलिस ने ग्राम भलपहरी, खरहट्टा, पांडातराई, सारंगपुर कला, कान्हाभैरा और दशरंगपुर में एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 13 बच्चों को अलग-अलग स्थानों से मुक्त कराया गया।

रेस्क्यू के बाद बच्चों को थाना लाकर पूछताछ की गई। बच्चों ने बताया कि उन्हें गांव से यह कहकर ले जाया गया था कि वहां काम के साथ अच्छा खाना और देखभाल मिलेगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उनसे लगातार मजदूरी कराई जाने लगी। बच्चों ने बताया कि उन्हें सुबह तड़के उठाकर मवेशियों के साथ जंगल भेज दिया जाता था। दिनभर की मेहनत के बाद भी उन्हें न तो मजदूरी मिलती थी और न ही पढ़ाई का कोई अवसर।

भड़के मनेंद्रगढ़वासी, बोतल में पानी लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे

■ बालोद जिले ने वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है.

मनेंद्रगढ़। जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। यहां के कई वार्डों में इन दिनों नलों से गंदगीयुक्त, मटमैला और बदबूदार पानी निकलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग अब नल का पानी पीने से डरने लगे हैं। नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में जब लगातार गंदा और सड़े बदबू वाला पानी सप्लाई होने लगा तो वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोग दूषित पानी को बोतलों में भरकर सीधे जल प्रदाय गृह पहुंच गए और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और जनता को पानी के नाम पर बीमारी परोसी जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर पालिका के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के बाद तत्काल दूषित पानी की सप्लाई बंद करवाई और जल विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई। उपाध्यक्ष ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की गुणवत्ता की जांच कर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद ही दोबारा सप्लाई शुरू की जाए। इंजीनियर और अधिकारियों ने बारिश के चलते पानी गंदा होने की बात कही है। वहीं लोगों का कहना है कि यदि जल गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही थी तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई।

नए शव वाहन का ना रजिस्ट्रेशन ना इंश्योरेंस, चार साल में बना कबाड, चिरमिरी नगर निगम पर उठे सवाल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चिरमिरी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा है। शहर में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लाखों रुपए की लागत से खरीदा गया शव वाहन रखरखाव की वजह से कबाड़ में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, सफाई व्यवस्था के लिए खरीदी गई कई मशीनें, ट्रैक्टर, कचरा वाहन, हाथ ठेले और उपकरण भी वर्षों से बेकार पड़े हैं।

चिरमिरी निगम ने चार साल पहले शहरवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नया शव वाहन खरीदा था। निगम का दावा था कि इससे अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को सम्मानजनक सुविधा मिलेगी। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कचरा उठाने वाली गाड़ियां, ट्रैक्टर, डस्टबिन, हाथ ठेले और कचरा नष्ट करने वाली मशीनें भी खरीदी गई थीं। इन संसाधनों पर लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन हैरानी की बात ये है कि खरीदारी के बाद से ही अधिकांश संसाधन उपयोग में नहीं लाए गए। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि चार वर्षों तक शव वाहन का न तो रजिस्ट्रेशन कराया गया और न ही उसका इंश्योरेंस हुआ। यानी जिस वाहन को जनता की सेवा में लगाया जाना था, वह कागजों की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण कभी सड़क पर उतर ही नहीं पाया।निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जनता में गुस्सा है।लोगों का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था लगातार बदहाल बनी रही, जगह-जगह गंदगी और कचरे की समस्या बनी रही, लेकिन दूसरी ओर सफाई के लिए खरीदी गई मशीनें और वाहन वर्षों तक एक ही जगह खड़े हैं।

भिलाई में चाकूबाजी के आरोपियों का निकला जुलूस

दुर्ग। जिले के भिलाई में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पुरानी रंजिश और गवाही का बदला लेने के लिए दो युवकों पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया था। छावनी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख शाहरूख समेत तीन आरोपियों को पकड़कर चौक पर उठक-बैठक भी लगवाई। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बुधवार शाम करीब 5.30 बजे आरोपियों का उनके ही मोहल्ले में जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस ने अपराध न करने की नसीहत दी। जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए। पुलिस ने आरोपियों से अपराध करना पाप है के नारे भी लगवाए। घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। जानकारी के मुताबिक घायल दोनों युवक आपस में दोस्त हैं और खाना खाने के बाद इलाके में टहलने निकले थे। इसी दौरान हाल ही में जेल से छूटा बदमाश शेख शाहरूख अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोपी पहले से युवकों से रंजिश रखता था और किसी पुराने मामले में उनके द्वारा गवाही देने से नाराज था। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि दोनों युवक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ट्रक चालक को स्टेपनी चोर समझ बंधक बनाकर पिटाई

एमसीबी। चिरमिरी निवासी ट्रक चालक धर्मेंद्र देवांगन ने वाहन मालिक और उसके साथियों पर बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने और अश्लील हरकत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित और उसके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चिरमिरी निवासी धर्मेंद्र देवांगन पेशे से ट्रक चालक है। ट्रक की स्टेपनी चोरी होने के शक में वाहन मालिक विकास शर्मा, मुकुल और उसके साथियों ने धर्मेंद्र को निशाना बनाया। धर्मेंद्र को पहले राउलकेला से एक कार में बैठाकर कोरबा लाया गया। इसके बाद उसे बस स्टैंड के पास स्थित एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि कमरे में उसे रस्सियों से बांध दिया गया और बेल्ट, डंडों और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा गया। मारपीट के दौरान उसके साथ अश्लील हरकत भी की गई। धर्मेंद्र के अनुसार आरोपियों ने घंटों तक उसे प्रताड़ित किया और लगातार धमकियां देते रहे। राउरकेला से कार में उठाकर कोरबा लाए।

स्वामी रामभद्राचार्य के आगमन से भक्तिमय हुआ बिलासपुर

बिलासपुर। बुधवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज बिलासपुर पहुंचे। यहां वे समाजसेवी प्रवीण झा के रामा वर्ल्ड स्थित निवास पर पहुंचे। रामभद्राचार्य के शहर पहुंचते ही आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह 9 बजे से ही निवास परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। भव्य स्वागत, वैदिक मंत्रोच्चार और भजन-कीर्तन के बीच चरण-पादुका पूजन का दिव्य आयोजन किया गया। लोगों ने उनकी पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान परिवार, मित्रों और श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया।स्वामी रामभद्राचार्य ने इस अवसर पर कहा कि जिस घर में संस्कार, सेवा और श्रद्धा का दीप जलता है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। परिवार और समाज के प्रति समर्पण ही सच्ची साधना है। उन्होंने प्रवीण झा परिवार की धार्मिक आस्था और सामाजिक सेवा की सराहना की। इस दौरान उन्होने प्रवीण झा से पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर आत्मीय चर्चा की। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

अवैध कोयला परिवहन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत रात्रि में कोटमी अड़भार क्षेत्र में कोयला परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान खनिज विभाग की टीम ने कोयले से भरे दो ट्रेलर वाहनों को रोका। इन वाहनों के क्रमांक MPv9ZF 2103 और MPv8ZF 2118 थे। चालकों से ई-ट्रांजिट पास प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने RPTP क्रमांक CGBLRPTP0134977/8 और CGBLRPTP0134977/7 प्रस्तुत किए। पूछताछ में चालकों ने बताया कि कोयला कुसमुंडा, कोरबा से लोड किया गया था। जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों में लोडिंग स्थल मां तारा ट्रेडर्स, रतनपुर (बिलासपुर) अंकित पाया गया। दस्तावेजों और वास्तविक जानकारी में अंतर पाए जाने पर मामला संदिग्ध हो गया। खनिज विभाग ने तत्काल दोनों ट्रेलर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की।

अवैध शौचालय निर्माण को लेकर विवाद,कार्रवाई की मांग

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत हिच्छा में कथित अवैध शौचालय निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। ग्रामीणों ने शासकीय भूमि और सार्वजनिक रास्ते के पास शौचालय का गड्ढा खोदे जाने का विरोध करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के शासकीय शिक्षक बुधराम पटेल द्वारा सीसी रोड किनारे और गली-मोहल्ले के बीच शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। इससे आसपास के लोगों में गंदगी, प्रदूषण और आवागमन में बाधा की आशंका बढ़ गई है। मामले को लेकर गांव के सरपंच, पंच और मोहल्लेवासियों ने पंचायत, पटवारी, तहसीलदार और थाना में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक भूमि के समीप इस प्रकार का निर्माण भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकता है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके का निरीक्षण भी किया है। वहीं स्थगन आदेश जारी किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है।

सीतामढ़ी की श्रीराम गुफा से मिलीं 14 दुर्लभ पांडुलिपियां

कोरबा। भारत सरकार के ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत कोरबा की श्रीराम गुफा मंदिर सीतामढ़ी से 14 दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियां मिली हैं। जिला प्रशासन ने इनका डिजिटल संरक्षण कर राष्ट्रीय अभिलेख में दर्ज कराया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित 'ज्ञानभारतम' राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत कोरबा में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का सशक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीराम गुफा मंदिर सीतामढ़ी से 14 अत्यंत दुर्लभ एवं प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। इनका डिजिटल संरक्षण कर राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखित किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा इस महत्वाकांक्षी अभियान को गंभीरता से क्रियान्वित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य देशभर में बिखरी प्राचीन एवं दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटल संरक्षण तथा भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित संवहन सुनिश्चित करना है।

सब्जी के खाली कैरेट के पीछे छिपाकर की जा रही थी 1.14 करोड़ गांजा तस्करी

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने एक पीकअप वाहन से 1.14 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया है, जिसे खाली कैरेट के पीछे छिपाया गया था और ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इसी के साथ ही टीम ने दो तस्करों को भी पकड़ा है। यह पूरा मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स की ओर से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी, एंड टू एंड एवं फाइनेशियल, सोर्स प्वाइंट, डेस्टीनेशन प्वाइंट पर प्रभावी और विधिवत कार्रवाई के निर्देश दिए

गए हैं। इसी के तहत जिले में पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इस बीच टीम को सूचना मिली कि तस्कर पीकअप क्रमांक MH16CD8741 में ओडिशा की ओर से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद टीम ने गनियारीपाली गांव ह॥ 53 रोड सिल्की ढाबा के सामने नाकेबंदी की। इस दौरान टीम ने मुखबिर के बताए पीकअप को रोक लिया और उसकी तलाशी लेने पर डाला में खाली कैरेट के बीच बोरियों में 226.600 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत 1 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपए आंकी गई।

वही टीम ने वाहन सवार दो तस्कर को भी पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम अजिनाथ आश्रु जाधव (28) और अक्षय बारुक (32) बताया। दोनों महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं। इसी के साथ ही आरोपियों ने बताया कि वो गांजा को ओडिशा के बालिगुड़ा से अहमदनगर लेकर जा रहे थे। टीम ने उनके पास से गांजा समेत पीकअप वाहन और 3 मोबाइल भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सिंघोड़ा थाने में धारा (20 बी) (दो) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ड्यूटी टाइम पर 35 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित, एसडीएम ने जारी किया नोटिस

तखतपुर। तखतपुर में शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम नितिन तिवारी के औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के 35 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर तलब किया गया है।

इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, एसडीएम नितिन तिवारी ने तखतपुर स्थित एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत और नगर पालिका कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी बिना अनुमति कार्यालय से नदारद पाए गए। उपस्थिति पंजी और बायोमैट्रिक

रिकॉर्ड की जांच में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कार्यालय समय में अनुपस्थित पाए गए सभी 35 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति और कार्यप्रणाली सुधारने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके तखतपुर क्षेत्र के कई दफ्तरों में लापरवाही का मामला सामने आया है। बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद भी कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से उपस्थिति दर्ज करने की शिकायतें मिली हैं।

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि नियमित रूप से कार्यालय न पहुंचने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन का सत्यापन किस आधार पर किया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

साय ने समाज प्रमुख को सौंपा टेंट एवं बर्तन सामग्री, आमगांव में बढ़ेगा रोजगार

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत खैरागढ़

वनमण्डल द्वारा रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई।वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के राज्य कैम्पा (क्षतिपूर्ति वर्गीकरण) मद से आस्थामूलक कार्यों के लिए ग्राम आमगांव के समाज प्रमुख श्री विष्णु ठाकरे को टेंट एवं बर्तन सामग्री प्रदाय की गई। बीते दिनों यह सामग्री मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के करकमलों से सौंपे जाने पर कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर सामाजिक एवं पारंपरिक आयोजनों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। समाज प्रमुख श्री विष्णु ठाकरे ने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गांव में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी और आय के नए साधन भी विकसित होंगे। इस पहल को ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक कदम बताया, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

केबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा का आज सारंगढ़ और झुमका दौरा'

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं

आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा शुक्रवार 08 मई 2026 को सारंगढ़-बिलाईगढ़ और झुमका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न सामाजिक और शासकीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री श्री टंक राम वर्मा सुबह 08.30 बजे रायपुर स्थित शासकीय आवास (शंकर नगर) से सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे और मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम (मण्डी प्रांगण) में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। दोपहर 1 बजे रेस्ट हाउस, सारंगढ़ में कार्यकर्ताओं से भेंट-मुलाकात करने के बाद दोपहर 03.15 बजे झुमका पहुंचेंगे और सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्व मंत्री शाम 5.30 बजे झुमका से वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे।

सुशासन तिहार 2026 से किसानों को मिल रहा वैज्ञानिक खेती का मार्गदर्शन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के माध्यम से किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शासन की पहल से अब कृषि विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर किसानों को उन्नत खेती की तकनीकों और मृदा परीक्षण के प्रति जागरूक कर रही है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर निवासी किसान श्री लालजी यादव ने कृषि विभाग के मार्गदर्शन में अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण कराया है। इससे अब उन्हें खेत की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की सही जानकारी मिल सकेगी और वे आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग कर सकेंगे। किसान लालजी यादव ने बताया कि पहले बिना जानकारी के खाद का उपयोग किया जाता था, जिससे लागत बढ़ती थी। अब मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेती करने से कम लागत में बेहतर उत्पादन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कृषि अधिकारी नियमित रूप से किसानों तक पहुंचकर वैज्ञानिक खेती की जानकारी दे रहे हैं, जिससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से किसानों को सीधे गांव में ही आवश्यक मार्गदर्शन और सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिल रही है।

सुशासन तिहार में अनीता को मिला नया राशन कार्ड

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है। शासन की संवेदनशील पहल से अब ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि प्रशासन स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहा है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम पंचायत मरेया निवासी श्रीमती अनीता को नया राशन कार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर ही राशन कार्ड जारी कर दिया गया। अनीता ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहले राशन कार्ड नहीं होने के कारण परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ नियमित रूप से मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनका काम हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर उप मुख्यमंत्री ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा-

'गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी', दोषियों पर कठोर कार्रवाई तय : अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, राज्य की कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था और विपक्षी दलों के आंदोलनों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक कथित रूप से नापाक हरकतों में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई तय है। साव ने दावा किया कि राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा न दिए जाने को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। साव ने कहा कि विपक्ष का ध्यान संविधान या लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं, बल्कि केवल अपने हितों पर रहता है। उन्होंने इसे सत्ता लोलुपता का उदाहरण बताया।

'ऑपरेशन सिंदूर' के एक वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश की सैन्य शक्ति का परिणाम था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए सरहद पर सक्रिय आतंकियों की ताकत को समाप्त किया गया और पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने दिया। उन्होंने सेना की बहादुरी को नमन किया।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई बड़ी प्रशासनिक नियुक्तियों और फेरबदल पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया

निर्णय है, जिससे शासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया।

सुशासन तिहार को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनता के प्रति जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि मंत्री और अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रशासनिक खामियों को दूर करने में मददगार साबित हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने एनएसयूआई द्वारा सीएम हाउस घेराव को लेकर उन्होंने कहा कि यह संगठन क्या करता है, यह सबको पता है। उन्होंने उनके आंदोलन को लेकर सवाल उठाते हुए उसकी मंशा पर भी टिप्पणी की।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हालिया बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भूपेश बघेल ने बीते बुधवार को कहा था कि वे श्रेय की राजनीति नहीं करते और उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो वे बंगाल और असम में मिली जीत का श्रेय लेकर दिखाएं। साथ ही उन्होंने ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए भाजपा की चुनावी जीत को लेकर टिप्पणी की थी।

इस बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यदि भूपेश बघेल कांग्रेस की हार से प्रसन्न हैं, तो यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 99 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस लगातार उत्साह में रहती है।

रायपुर में घर से बम बनाने की सामग्री मिलने से हड़कंप

धनेंद्र साहू ने कहा- सरकार को तय करनी चाहिए जवाबदेही

रायपुर। राजधानी के रावाभाठा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब वार्ड नंबर 13 स्थित एक घर से संदिग्ध बम बनाने की सामग्री मिलने की सूचना सामने आई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यहां से तार, संदिग्ध केमिकल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद होने की बात कही जा रही है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर नाकाबंदी कर पुलिस बल तैनात किया गया है।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के लोगों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है।

बता दें कि यह इलाका रायपुर कमिश्नरेट के नार्थ जोन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस ने मौके पर मिले संदिग्ध सामान की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा

रही है कि यह सामग्री किस उद्देश्य से रखी गई थी।

फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।

विपक्ष कर रहा अशांति फैलाने की कोशिश : उपमुख्यमंत्री साव

राजधानी रायपुर के रावाभाठा इलाके में संदिग्ध बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिलने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस घटना पर डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद विपक्षी दलों की ओर से प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकार पूरी तरह सजग है और किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है और केवल कांग्रेस को दोष देने में लगी है। उनके अनुसार यह घटना प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है और सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए।

वंदे मातरम' को वैधानिक संरक्षण देना राष्ट्र की आत्मा का सम्मान: साय

■ 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरव को मिला नया सम्मान'

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रभक्ति की भावना को सम्मान देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और आत्मसम्मान का विषय है।

उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' भारत की आत्मा, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा और करोड़ों देशवासियों की राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री

ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान 'वंदे मातरम' ने देशवासियों में नई ऊर्जा और आत्मबल का संचार किया था। यह गीत आज भी हर भारतीय के मन में मातृभूमि के प्रति समर्पण, सेवा और गौरव की भावना जागृत करता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार निरंतर भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय गौरव और जनभावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान एवं गरिमा को बनाए रखने का आह्वान भी किया।

सिंहदेव पीसीसी चीफ बनने तैयार, सबको साथ लेकर चलना मेरी प्राथमिकता होगी

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने तैयार हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपता है तो वे इस पद को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सिंहदेव ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, भेदभाव कम से कम रहे, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए संगठन के हर स्तर पर संवाद और समन्वय बढ़ाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए रखने और सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया।राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आने वाले समय में संगठनात्मक फेरबदल की संभावना को देखते हुए सिंहदेव का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। उनके इस संकेत के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है।बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। जारी आदेश के अनुसार, संगीता सिन्हा आगामी स्थायी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। संगठन में यह बदलाव आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

संगीता सिन्हा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने से महिला कांग्रेस में नए सिरे से सक्रियता आने की उम्मीद जताई जा रही है।पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा।

देवरीकला में उमड़ा जनसैलाब, आवेदनों का हुआ त्वरित निपटारा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन संकल्प को धरातल पर उतारते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम पंचायत देवरीकला में विशाल जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में 14 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया, जहाँ प्रशासन ने न केवल शिकायतें सुनीं, बल्कि मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी वितरित किया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों ने सक्रियता दिखाते हुए हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभान्वित किया गया। राजस्व विभाग ने 9 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख, खसरा और किसान किताब का वितरण किया। इसी प्रकार 5 परिवारों को उनके सपनों के पक्के घर प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियाँ और प्रमाण पत्र सौंपे ।

परिवहन विभाग द्वारा 14 ग्रामीणों को मौके पर ही ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए गए। महिला एवं बाल विकास ने 5 गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं 4 बच्चों का अन्नप्राशन किया और 17 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा । मत्स्य पालन विभाग द्वारा महाजाल,कैरेट वितरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी पोषण किट और दिव्यांगों को सहायक उपकरण (छड़ी) दिए गए।

मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत पहाड़ी कोरवा बसाहटों में 113 हैंडपंप व बोरवेल की होगी खुदाई

रायपुर। सरगुजा जिले के सुदूर एवं पहाड़ी कोरवा बसाहटों में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इन क्षेत्रों में कुल 113 हैंडपंप एवं बोरवेल की खुदाई की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को पारंपरिक स्रोतों से पानी लाने की मजबूरी से राहत मिलेगी।विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले में पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि शासन की योजनाओं खासकर बुनियादी जरूरतों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना यह सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

कमांक/जि.चि./जीवनदीप/निविदा-कैटिन /2026-27/ बेमेतरा, दिनांक:-../04/2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 (01 वर्ष हेतु) हेतु कैंटिन एवं धर्मशाला संचालन के लिये स्थानीय निविदा आमंत्रण

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

निविदा प्रपत्र 1000.00 रू. नगद जमा कर प्राप्त करने की अंतिम तिथि	20.05.2026 (दोप. 02 बजे तक)
निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट से जमा करने की अंतिम तिथि	25.05.2026 (दोप. 12:00 बजे तक)
निविदा खोलने की तिथि	25.05.2026 (दोप. 04:00 बजे)

निविदा प्रपत्र 8 पन्नों का रहेगा, जिसमें संज्ञान अधिकारी का सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर रहेगा। यदि नहीं रहेगा तो मान्य नहीं होगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

सिविल सर्जन सह सचिव जीवनदीप समिति
जिला चिकित्सालय बेमेतरा

जी-262700559/5

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद

Phone No.: 07749-222370, Email Id : ee-res.balod@gov.in

(E-Tender) सूचना प्रथम बार

क्रमांक / 01 /व.ले.लि./ग्रा.यां.से./2026-27 बालोद, दिनांक 07.05.2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में "डी"-वर्ग एवं उच्च श्रेणी में ठेकेदारों पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र-"अ" पर दर्शित कार्य हेतु प्रतिशत दर प्राप्त करने ऑनलाईन ई-निविदा दिनांक 21.05.2026 तक आमंत्रित की जाती है। कार्य पूर्ण करने की अवधि 08 माह वर्षात्रद्धु

क्रमांक	कार्य का नाम एवं स्थल	ठेके की अनुमानित लागत लाख में	धरोहर राशि रु. में
1	2	3	4
	राजाराव पठार मेला स्थल पर मंच एवं मंच के सामने डोम निर्माण कार्य ग्राम एवं ग्राम पंचायत करेंझर विकासखण्ड गुरूर	66.31	66310/-

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in में दिनांक 07.05.2026 से देखी जा सकती है ।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

जी-262700581/4

ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने वीर सैनिकों को किया नमन

नया भारत अब आतंकवाद को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने वाला नहीं है : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि यह अभियान केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नए भारत की अटूट इच्छाशक्ति, निर्भीक संकल्प और निर्णायक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज से एक वर्ष पूर्व पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों द्वारा किए गए घिनौने हमले ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया था, लेकिन भारत ने उस चुनौती का ऐसा जवाब दिया, जिसने इतिहास में शौर्य और संकल्प का स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि

ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि नया भारत अब आतंकवाद को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत चुपचाप सहने वाला राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि मातृभूमि की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का निर्णायक और प्रभावशाली जवाब देने में सक्षम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, बेजोड़ रणनीति और राष्ट्र के प्रति असीम समर्पण को अमर कर दिया। जिस सटीकता, दृढ़ता और प्रभावशाली क्षमता के साथ आतंक के सरपरस्तों और उनके आकाओं को जवाब दिया गया, उसने वैश्विक मंच पर भारत की सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व की नई पहचान स्थापित की।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर सिद्ध भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं की संयुक्त शक्ति, अत्याधुनिक युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक और प्रभावी प्रतिकार भी करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर राष्ट्र के उन सभी वीर सपूतों को कोटिशः नमन किया, जिनके शौर्य और पराक्रम ने हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊँचा किया है। उन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय सेना का पराक्रम, राष्ट्रभक्ति और बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

सत्ता के लिए पाला बदलने में कांग्रेस को नहीं होती हिचक

नीरज कुमार दुबे

तमिलनाडु की राजनीति में आज एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिला, जब कांग्रेस ने विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम यानि टीवीके को सरकार गठन के लिए समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस फैसले के साथ ही द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानि द्रमुक और कांग्रेस के बीच दो दशक से अधिक पुराने राजनीतिक रिश्ते पर लगभग विराम लग गया है। कांग्रेस ने साफ किया है कि उसका यह गठबंधन केवल सरकार गठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय निकाय, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों तक जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके 234 सदस्यीय सदन में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस के पांच विधायकों के समर्थन के बाद यह संख्या 113 तक पहुंच गई है और अब सरकार गठन के लिए केवल पांच और विधायकों की आवश्यकता रह गई है। विजय ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कांग्रेस ने अपने समर्थन के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। पार्टी ने कहा है कि टीवीके किसी भी परिस्थिति में भाजपा या उसके सहयोगी दलों को सरकार या गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएगी। तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडानकर ने कहा कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और संवैधानिक मूल्यों वाली राजनीति के साथ खड़ी है और जनता के जनादेश का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। उधर, कांग्रेस के इस फैसले ने द्रमुक को गहरा राजनीतिक झटका दिया है। द्रमुक नेताओं ने इसे ''पीठ में छूरा घोंपना'' बताया है। यह नाराजगी इसलिए भी अधिक है क्योंकि द्रमुक और कांग्रेस का रिश्ता केवल चुनावी समझौता नहीं बल्कि लंबे समय की राजनीतिक साझेदारी माना जाता रहा है। दोनों दल पहली बार 1971 में साथ आए थे और बाद में 2004 से 2013 तक द्रमुक केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का अहम हिस्सा रही थी। 2016 के बाद दोनों ने फिर मिलकर चुनाव लड़े और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी राजनीति की मजबूत धुरी बने। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस और द्रमुक तमिलनाडु में आमने सामने होंगे, तब क्या वह राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर बने रह पाएंगे। कांग्रेस यह तर्क दे रही है कि वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस की तरह अलग अलग राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद इंडिया गठबंधन जारी रह सकता है। लेकिन द्रमुक की नाराजगी और कांग्रेस के नए रुख ने विपक्षी एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ विजय और उनकी पार्टी टीवीके को मिलता दिखाई दे रहा है। पहली बार चुनाव लड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनना और उसके तुरंत बाद कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल का समर्थन हासिल करना विजय को राज्य की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करता है। यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई स्थित सत्यमूर्ति भवन में जश्न मनाया और इसे नई राजनीतिक शुरुआत बताया। विजय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से बात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित भी किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों दल भविष्य में स्थायी राजनीतिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि विजय ने राहुल गांधी और खरगे को फोन कर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

चुनाव : मोदी-शाह की जोड़ी का तोड़ नहीं

मुस्ताअली बोहरा

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों ने भारतीय राजनीति की तस्वीर ही बदल दी है। मोदी-शाह की जोड़ी ने फिर ये साबित कर दिया किया कि इनसे पार पाना आसान नहीं होगा। हालांकि, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद वोट चोरी, चुनाव चोरी, फर्जी वोटिंग सहित बाहुबल और धन बल का इस्तेमाल किए जाने के आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। जो भी हो, बंगाल फतेह ने असम में बीजेपी की हैट्रिक का मजा दोगुना कर दिया है। पुडुचेरी में दूसरी बार एनडीए सरकार की आई है। बीजेपी ने अपना अगला टारगेट भी सेट कर दिया है वो है पंजाब। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की बहुमत से जीत का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी नजर आएगा। बंगाल की जीत ने तो ये भी जता दिया है कि मोदी-शाह की जोड़ी ही चुनावी जीत का असल मंत्र है। जिस राज्य के चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ होगा, एंटी इनकमबेंसी होगी, सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट होगी वहां मोदी की चुनावी सभा और शाह की रणनीति निर्णायक साबित होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की चुनावी सभा में कहा था कि बंगाल जीतने के साथ बीजेपी अपना अंग, बंग और कलिंग जीतने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। अंग मतलब बिहार, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी ओडिशा। असम में सत्ता की वापसी और पश्चिम बंगाल में जीत ने बीजेपी की स्थिति को पूर्व और पूर्वोत्तर में मजबूत किया है। इस जीत से बीजेपी के एमएलए तो बढ़ेंगे ही साथ राज्यसभा में भी भाजपा सांसदों की गिनती बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ, इन चुनावी नतीजों ने जाहिर कर दिया कि विपक्ष में एकजुटता की कमी है, वो चुनाव में कोई ऐसा मुददा नहीं खड़ा कर पाता जो मतदाताओं को रिझा सके। साथ ही बिना स्पष्ट नेतृत्व और मजबूत अजेंडा के बीजेपी का मुकाबला करना आसान नहीं है। अब, दिगर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और साल 2029 के लोकसभा चुनाव में इस जीत की गूंज बरकरार रहेगी।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इतनी तगड़ी जीत की उम्मीद तो खुद ममता बनर्जी को भी नहीं रही होगी। जानकारों का मानना है कि डेढ़ दशक तक सीएम रहीं ममता ने जो बोया था वही काटा है। टीएमसी के वोटों का बिखराव, एंटी इम्कमबेसी, भाजपा की बूथ स्तर पर रणनीति,

एसआईआर का प्रभाव, वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम कटने को भी हार का कारण माना जा रहा है। मालूम हो कि कोई डेढ़ दशक पहले यही ममता, बीजेपी को अपना सहयोगी मानतीं थी। विश्लेषकों का मानना है कि ममता ने अपनी पराजय का बीज खुद ही बोया था। जुलाई 2022 में ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का साथ देने से मना कर दिया। बाद में ममता बनर्जी के सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया इससे जगदीप धनखड़ जीत गए। ममता बनर्जी ने एक तरह से धनखड़ की मदद की। इसके बाद इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद पर नितिश कुमार को नियुक्त करने का ममता बनर्जी ने तीखा विरोध किया था। शायद इसी वजह से नितीश कुमार नाराज हो गए थे और बाद में वे भाजपा के साथ चले गए। सन 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इंकार करके अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष का वोट बैंक बिखरा जिसका फायदा बीजेपी को मिला। विपक्ष की टूट का असर ये हुआ कि बीएसपी, बीजेडी, आप, टीआरएस, वायआरएस, पीडीपी जैसे दल राजनीतिक अस्तित्व बचाते दिख रहे हैं। यहां बता दें कि साल 1997 में कांग्रेस तोड़ कर मुकुल रॉय के साथ ममता ने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। बाद में मुकुल राय भाजपा में चले गए लेकिन सन 2021 के विधानसभा चुनावों के पहले वो टीएमसी में वापस आ गए।

साल 2019 में ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीएए की खिलाफत तो की लेकिन जब सीएए पर संसद में मतदान हुआ तो टीएमसी के आठ सांसद गैरहाजिर रहे और इस वजह से विधेयक पारित हो गया। जब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार रैली निकल रही थी तब इसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं हुईं थीं। खैर, ये बात और है कि ममता को इस बात का गुमान ही नहीं रहा होगा कि जिस भाजपा को वो सपोर्ट कर रही है एक दिन वही उसे सत्ता से बेदखल कर देगी। बीजेपी अब 2029 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी लोस सीटों पर जीत की कोशिश करेगी।

विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और फिर तृणमूल कांग्रेस केन्द्र में बड़ी पार्टियों में है। कांग्रेस के 99, सपा के 37 और टीएमसी के 29 सांसद हैं। बंगाल और असम में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की तो केरलम में कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ ने सत्ता में वापसी की। तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन को भी हार का सामना करना पड़ा, यहां फिल्म एक्टर विजय की टीवीके ने जीत हासिल की। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सहित विपक्ष के कई बड़े नेता हार गए। इसके साथ ही अब लोगों की नजरें इस बात भी टिकी हैं कि ममता और स्टालिन की फाइलें कब से खुलना शुरू होतीं हैं। यहां बता दें कि इससे कुछ महीने पहले ही भाजपा ने बिहार में अपना पहला सीएम बनाया, सम्राट चैधरी के रूप में बीजेपी को यहां अपना पहला मुख्यमंत्री मिला। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी ने सत्ता वापस हासिल की। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम और अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में गठबंधन सरकार है। निश्चित रूप से बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा और अब वह उन राज्यों में भी चुनावी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी जहां अभी उसकी पकड़ कमजोर है। इधर, इंडिया गठबंधन भी असरकारक साबित नहीं हुआ। इसके गठन के कुछ ही महीनों बाद से ही इसमें टूट होने लगी थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तब इस गठबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सीएम ममता बनर्जी, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, सपा नेता अखिलेश यादव, आप नेता अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन बना तो सही लेकिन चल नहीं पाया। कुछ ही अंतराल बाद नितिश कुमार ने गठबंधन छोड़ दिया और बीजेपी से गलबहिया कर लीं। लोकसभा चुनाव के पहले सीट बटवारे को लेकर गठबंधन के दलों के बीच दिल नहीं मिले। आप और कांग्रेस के बीच तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच पटरी नहीं बैठी। नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन नाम का होकर रह गया।

चुनाव में पार्टी की हार दुखद तो होती ही है लेकिन असल रंज तब होता है जब सत्ता में काबिज सीएम अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। हाल ही के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी सीएम रहते हुए भी अपनी भवानीपुर सीट नहीं बचा पाईं। उन्हें भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने तकरीबन 15 हजार वोटों से शिकस्त दी। इससे पहले सन 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु से हार चुकीं थी। ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेता बन गई हैं जो सीएम रहते हुए लगातार दूसरी बार हारीं। उधर तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन को भी कोलाथुर सीट से थलपति विजय की पार्टी टीवीके के वीएस बाबू से पराजित हो गए। दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी अपनी सीट गंवा चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम रहते हुए हरीश रावत सन 2017 विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीटों से हार गए थे। उत्तराखंड में सन 2022 विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी भी सीएम रहते हुए विधानसभा चुनाव हार गए थे। पंजाब के सीएम रहते हुए चरण जीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और भदौर दो सीटों से पर्चा भरा था लेकिन वो हार गए थे। गोवा के लक्ष्मीकांत पारसेकर साल 2017 में कांग्रेस के दयानंद सोप्ते ने उन्हें हरा दिया था। कुल मिलाकर चुनाव में यदि कोई सीएम अपनी ही सीट नहीं बचा पाए तो हैरत होना स्वाभाविक है। हालांकि, सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता चुनाव हारते रहे हैं फिर चाहे वो किसी राज्य में मंत्री रहे हों या केन्द्र में।

बहरहाल, अब इंडिया गठबंधन को रिफार्म करने की जरूरत है ताकि एक मजबूत विपक्ष बन सके। छोटे दलों को कांग्रेस का समर्थन करना होगा। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, आप, पीडीपी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों को अपनी महत्वकांक्षा से इतर सोचना होगा। विपक्ष को चाहिए कि वो चुनावी का हार का मंथन करते हुए आगे बढ़े। अपनी गलतियों से सीख ले, जनता की बीच लगातार संपर्क बनाए रखते हुए जनहित के मुद्दों को उठाते रहे। राजनीति में सत्ता परिवर्तन कोई होना कोई नया नहीं है लेकिन जो जनविश्वास जीतेगा वही सत्ता हासिल करेगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

वास्तविक भाव

उपर्युक्त दोनों स्वरूपों की तुलना करने पर प्रत्येक साक्षर इस आख्यान की वैदिकता का अच्छी तरह अनुमान कर सकता है। कई क्षुद्रबुद्धि लन इस कथा से नियोग भी सिद्ध करना चाहा करते हैं, परन्तु उन्हें यह विदित नहीं कि इससे तो आप के भाने हुये नियोग की उल्टी धज्जियें उड़ जाती हैं। क्योंकि आपके यहाँ नियोग का लक्षण यही तो है कि सन्तान के लिए पति की आज्ञा से या उसके मरने पर किसी परपुरुष से इच्छापूर्वक भोग करना। उक्त कथा में इन तीनों बातों का सर्वथा अभाव है। क्योंकि सन्तान तो पूर्व ही ममता के गर्भ में विद्यमान थी। पति आज्ञा का इसमें लेशमात्र भी नहीं और ममता अन्त तक इस कार्य के सर्वथा प्रतिकूल ही रही है। अतः इसे खुला व्यभिचार या बलात्कार ही कह सकते हैं। अगर आप की सम्मति में नियोग भी इसी का का नाम है तब तो आप के इस धार्मिक कृत्य पर सौ-सौ बार बलिहारी! आशा है कि प्रतिवादी अब इससे नियोग सिद्ध करने का साहस नहीं दिखायेंगे। रहा इसकी वास्तविकता का विचार, सो हम वैदिक शब्दों में ही प्रकट करते हैं। वेदों में लिखा है कि-

(क) वाग्वै बृहती

(शतपथ 14 । 4 । 1 । 22)

(ख) पतिः पालयिता

(निरुक्त अ0 10 खं0 21)

अर्थात् (क) यह वाक् ही बृहती कही जाती है। (ख) पति रक्षक को कहते हैं।

सो पुरुष का मन ही बृहस्पति कहलाता है क्योंकि यन्मनसाऽनुमनुते तेदू बाचा वदति इस श्रुति के अनुसार पहिले मन में जो भाव उदित होता है वही पश्चात् वाणी से बोला जाता है। अतः मनः ही वाणी का पति कहला सकता है। इसका ज्येष्ठ भ्राता जीवात्मा ही उतथ्य है।

क्रमशः ...

विश्व रेड क्रॉस दिवस

दिलीप कुमार पाठक

आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हमारे पास अपनों के लिए भी ठीक से वक्त नहीं है, तब दुनिया में एक ऐसा संगठन भी काम कर रहा है, जिसे न नाम का लालच है और न ही किसी इनाम का। इनका बस एक ही मकसद है। जहाँ मुसीबत हो, वहाँ मदद बनकर पहुँच जाना। हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस की। हर साल 8 मई को जब हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, तो यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि उस जज्बे को सलाम करने का दिन है जो युद्ध के मैदान से लेकर प्रकृति के कहर तक, हर जगह इंसानियत की ढाल बनकर खड़ा रहता है। इस संस्था की शुरुआत की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। करीब 165 साल पहले इटली में एक भीषण युद्ध हो रहा था, हज़ारों सैनिक घायल होकर तड़प रहे थे। वहीं से गुजर रहे स्विट्जरलैंड के कारोबारी हेनरी डुनेंट से यह दुख देखा नहीं गया। उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया और गांव वालों को जुटाकर घायलों की सेवा में लग गए। उन्होंने एक ही बात कहा हम सब भाई हैं। यही छोटी सी सोच आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन रेड क्रॉस बनी।

आज हेनरी डुनेंट के जन्मदिन पर ही पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। भारत में इस महान संस्था का सफर भी बहुत प्रेरणादायी रहा है। साल 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था, और तब से लेकर आज तक यह हमारे देश की हर बड़ी मुश्किल में भरोसे का दूसरा नाम बनी हुई है। चाहे 1947 का वो मुश्किल दौर हो या फिर केदारनाथ की त्रासदी और भुज का भूकंप, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने हमेशा आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है।

आंकड़ों की बात करें तो आज रेड क्रॉस का हाथ दुनिया के 192 देशों तक फैला हुआ है। करीब 1.6 करोड़ से ज्यादा वॉलंटियर्स इस मिशन से जुड़े हैं। अकेले भारत में ही इसकी 1100 से ज्यादा शाखाएं दिन-रात काम कर रही हैं। कोरोना का वो दौर तो हम सबको याद ही है, जब लोग एक-दूसरे से हाथ मिलाने तक से डर रहे थे। उस मुश्किल वक्त में रेड क्रॉस के साथी ही थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर घर-घर राशन और दवाइयां पहुँचा रहे थे। रेड क्रॉस का काम केवल जोश पर नहीं, बल्कि सात मजबूत सिद्धांतों पर टिका है, जिन्हें इसकी आत्मा कहा जाता है। ये सिद्धांत हैं - मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। ये भारी-भरकम शब्द सुनने में भले ही कठिन लगें, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। रेड क्रॉस किसी की मदद करते समय यह नहीं देखता कि सामने वाला किस धर्म का है या किस देश का है। इसके लिए हर वो इंसान बराबर है जो पीड़ित है। यह संस्था किसी भी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ती, ताकि यह हर जगह बेखौफ जा सके। रेड क्रॉस सिर्फ आपदा के समय ही नहीं दिखता, बल्कि हमारे आसपास एक शांत सैनिक की तरह हमेशा मौजूद रहता है। चाहे वह गरीबों के लिए सस्ती दवाइयां हों, थैलेसीमा पीड़ित बच्चों के लिए सुरक्षित खून का इंतजाम करना हो या फिर एक्सीडेंट के समय दी जाने वाली प्राथमिक सहायता - रेड क्रॉस हर मोड़ पर खड़ा मिलता है।

जितनी बड़ी जीत भरोसे पर खरा उतरने की उतनी बड़ी चुनौती!

मनोज कुमार अग्रवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नौ मई को भाजपा सरकार की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस चुनाव ने राज्य को राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राज्य में यह सत्ता बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक और सामाजिक बदलाव की आहट भी हैं। जितना लंबे समय तक ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता था।

2011 में वाम शासन को समाप्त कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को अपनी शैली, अपनी भाषा और अपने संगठन के बल पर चलाया। लेकिन इस बार के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक किला स्थायी नहीं होता। मतदाता जब बदलाव का मन बना लेता है, तो सबसे मजबूत शासन भी कमजोर पड़ सकता है। मतगणना के बाद अनुसार भाजपा ने 206 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस काफी पीछे रह कर सिर्फ 81 सीट पर जीत हासिल कर सकी है । बंगाल का राजनीतिक इतिहास संघर्ष, विचारधारा और जनभावना से भरा रहा है। कभी वामपंथी राजनीति का मजबूत किला रहे इस राज्य में बाद के वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। ममता बनर्जी ने लंबे समय तक खुद को बंगाल की जनता की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता समय-समय पर सत्ता को परखती है और आवश्यकता पड़ने पर बदलाव का निर्णय भी करती है। इस चुनाव में सामने आए रक्षान बताते हैं कि जनता ने विकास, रोजगार, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दों पर गंभीरता से मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह परिणाम अभूतपूर्व है, क्योंकि जिस राज्य में कभी पार्टी की उपस्थिति सीमित मानी जाती थी, वहां बहुमत की

दहलीज तक पहुंचना संगठनात्मक विस्तार, बूथ स्तर की तैयारी और राजनीतिक रणनीति की सफलता को दर्शाता है। भाजपा ने पिछले वर्षों में बंगाल के ग्रामीण इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों, चाय बागान क्षेत्रों, मतुआ समाज, आदिवासी इलाकों और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की। इस चुनाव में उस मेहनत का असर रुझानों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय है। हकिकत यह कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए लंबे समय तक सत्ता में बने रहना एक बड़ी चुनौती होता है। समय के साथ सत्ता के प्रति जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। यदि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर लोगों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, तो असंतोष धीरे-धीरे जनादेश में बदल जाता है। बंगाल में भी एंटी-इंकंवेंसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रतीत होती है। तृणमूल के कई मजबूत नेताओं की हार या पिछड़ना इस बात का संकेत है कि जनता ने केवल पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि स्थानीय प्रदर्शन और जनसंपर्क के आधार पर भी मतदान किया है। इस बदलाव की पहली बड़ी वजह मतदाता सूची की पुनर्समीक्षा रही। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद राज्य की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटाए गए है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में बड़ी संख्या में नाम हटे, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के मजबूत इलाकों में गिना जाता रहा है। चुनाव आयोग की दृष्टि से यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसका असर बहुत गहरा दिखाई दिया। टीएमसी का पारंपरिक सामाजिक समीकरण कमजोर पड़ा और भाजपा को इसका लाभ मिला। दूसरी अहम वजह बंगाली अस्मिता की लड़ाई रही। ममता बनर्जी लंबे समय से भाजपा को बाहरी बताकर बंगाल की की संस्कृति, भाषा और खानपान से जोड़कर राजनीति करती रही हैं। लेकिन भाजपा ने इस बार इस प्रतीक को अपने खिलाफ हथियार बनने नहीं दिया। उसने यह संदेश देने की कोशिश की कि उसका हिंदुत्व बंगाल की संस्कृति से टकराता नहीं, बल्कि बंगाल की शाक्त परंपरा, मां काली की उपासना और स्थानीय जीवनशैली के साथ चल सकता है। यही वह मोड़ था जहां ममता बनर्जी का सांस्कृतिक एकाधिकार कमजोर पड़ा। तीसरी वजह पहचान और ध्रुवीकरण की राजनीति रही। बंगाल में पहले भी धार्मिक पहचान चुनावी विमर्श का हिस्सा रही है, लेकिन इस बार भाजपा ने इसे अधिक आक्रामक ढंग से उठाया। तृणमूल कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए भाजपा ने हिंदू मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश की। काली बनाम काबा जैसे नारों ने चुनावी बहस को भावनात्मक और धार्मिक पहचान की दिशा में मोड़ दिया। यह राजनीति विवादास्पद हो सकती है, लेकिन चुनावी दृष्टि से इसका असर साफ दिखा। जिन इलाकों में हिंदू मतों का बिखराव था, वहां भाजपा ने उन्हें अपने पक्ष में संगठित करने में सफलता पई। चौथी वजह युवा मतदाताओं की आकांक्षा रही। बंगाल का एक बड़ा युवा वर्ग पिछले पंद्रह वर्षों से तृणमूल शासन के वातावरण में बड़ा हुआ। इस पीढ़ी के सामने सवाल केवल नकद सहायता योजनाओं या स्थानीय लाभों का नहीं था, बल्कि रोजगार, उद्योग, निवेश और बेहतर भविष्य का था। भाजपा ने सोनार बांग्ला और डबल इंजन सरकार के नारे के जरिए इसी आकांक्षा को छुआ। यह संदेश दिया गया कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से निवेश, आधारभूत ढांचा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। मतुआ समुदाय के बीच नागरिकता के मुद्दे को उठाकर भाजपा ने एक और महत्वपूर्ण सामाजिक आधार को अपने पक्ष में मजबूत किया। पांचवीं वजह कांग्रेस और वाम दलों की राजनीतिक अनुपस्थिति रही। बंगाल की राजनीति कभी वामपंथ का गढ़ थी। कांग्रेस भी लंबे समय तक राज्य में प्रभावशाली रही। लेकिन इस चुनाव में मुकाबला लगभग सीधे भाजपा और टीएमसी के बीच सिमट गया। जब तीसरी ताकत कमजोर हो जाती है, तो सत्ता विरोधी वोट सीधे सबसे मजबूत विपक्षी दल को मिलते हैं। भाजपा को यही लाभ मिला। 2021 में जिन सीटों पर भाजपा मामुली अंतर से हार गई थी, इस बार वोट स्विंग ने उन सीटों को उसके पक्ष में मोड़ दिया। हालांकि इस जनादेश को केवल भाजपा की जीत और तृणमूल की हार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह बंगाल के मतदाता का संदेश भी है कि कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन वे शासन की कमियों, रोजगार की कमी, भ्रष्टाचार के आरोपों और संगठनात्मक अहंकार की भरपाई हमेशा नहीं कर सकीं। ममता बनर्जी ने बंगाल को वाम शासन से बाहर निकालकर नई दिशा दी थी, लेकिन लंबी सत्ता अपने साथ थकान भी लाती है। सत्ता जब संगठन से बड़ी हो जाती है, तो जनता विकल्प तलाशने लगती है। भाजपा के लिए यह जीत जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। बंगाल केवल एक चुनावी राज्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक चेतना की भूमि है। यहां शासन करना केवल बहुमत से संभव नहीं होगा। भाजपा को यह साबित करना होगा कि वह बंगाल की भाषा, संस्कृति, विविधता और सामाजिक संतुलन का सम्मान करते हुए विकास का मौडल दे सकती है। यदि वह केवल ध्रुवीकरण तक सीमित रही, तो यह जनादेश जल्द ही चुनौती में बदल सकता है। बंगाल का यह चुनाव बताता है कि लोकतंत्र में कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। जनता चुप रहती है, देखती है, परखती है और समय आने पर फैसला सुनाती है। 2026 के इसी फैसले की गूंज हैं।

आज का इतिहास

1736 फ्रेडरिक जो के वेल्स के राजकुमार थे, ने सक्से-गोथ की राजकुमारी अगस्ता से शादी की।
1741 फ्रांस और बवेरिया ने निम्फ़ेनबर्ग के करार पर हस्ताक्षर किया।
1773 मिस्र में, ओट्टोमैन विद्रोहियों ने विद्रोह किया, मिस्र के मल्लुक सुल्तान अली बे की हत्या कर दी।
1842 पेरिस में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई, जिसमें 52 और 200 लोग मारे गए।
1847 रबर टायर को रॉबर्ट डब्ल्यू. थॉम्पसन ने पेटेंट करवाया।
1863 अमेरिकी नागरिक युद्ध: सैन्य संघ द्वारा पोर्ट हडसन, लुइसियाना की घेराबंदी शुरू की।
1886 अटलांटा में, अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने पहले एक पेटेंट दवा के रूप में अपने कार्बोनेटेड पेय कोका-कोला को बेचा, यह दावा करते हुए कि यह कई बीमारियों को ठीक करता है।
1898 इटली फुटबॉल लीग के पहला खेल खेला गया।
1921 स्वीडन ने फांसी की सजा को खत्म कर दिया।
1924 लिथुआनिया ने राजदूतों के सम्मेलन के राष्ट्रों के साथ क्लेपेडा समझौते पर हस्ताक्षर किए, ईस्टप्रासिया से क्लेपेडा क्षेत्र को लिया और लिथुआनिया के बिना शर्त वाले क्षेत्र में एक स्वायत्त क्षेत्र में बना दिया।
1927 फ्रांसीसी एविएटर्स चार्ल्स नुंगेसर और फ्रैंकोइस कोली अबोर्डल ओसेऊ ब्लैंक बाइप्लेन, पेरिस से न्यूयॉर्क के लिए पहली गैर-स्टॉपट्रांसलेटिक उड़ान बनाने का प्रयास करते हैं, टेकऑफ़ के बाद गायब हो गए।
1945 यूरोप दिवस में विजय या बस वी-ई दिवस के रूप में जाना जाता है पहली बार यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को चिह्नित करने के लिए 8 मई, 1945 को मनाया गया था।
1956 ऑस्ट्रिया और इसराइल राजनयिक संबंधों को बढ़ाया।
1963 दक्षिण वियतनाम, वियतनाम गणराज्य की सेना के सैनिकों ने बौद्ध प्रदर्शनकारियों की भीड़ के खिलाफ वेसाखा में बौद्ध ध्वज के उड़ने पर प्रतिबंध लगाने, बौद्ध संकट को मारने और भड़काने के लिए आग लगा दी।
1970 बीटल्स ने अपने 12 वें और अंतिम एल्बम जाने भी दो को जारी किया।
1970 न्यूयॉर्क शहर में निर्माण श्रमिकों ने केंट राज्य की गोलीबारी का विरोध कर रहे छात्रों और माताओं पर हमला किया।
1972 ब्लैक सितंबर के चार सदस्यों ने 315 दोषी ठहराए गए फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रिहाई की मांग करने के लिए सबीना फ्लाइट 571 को अपहृत किया।

इंडी में बिखराव का खतरा: विपक्ष के लिए आत्ममंथन का समय

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी अनिवार्य भूमिकाएं हैं। जहां सत्ता नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करती है, वहीं विपक्ष उन नीतियों की समीक्षा, संतुलन और वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। लेकिन जब विपक्ष स्वयं ही असंगठित, दिशाहीन और अंतर्विरोधों से ग्रस्त हो जाए, तब लोकतांत्रिक संतुलन भी प्रभावित होता है। हाल के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी एकता का दावा करने वाला गठबंधन अपने भीतर ही गंभीर संकट से गुजर रहा है।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की पराजय और तमिलनाडु में द्रमुक की स्थिति ने विपक्षी खेमे को झकझोरने का काम किया है। यह केवल चुनावी हार नहीं है, बल्कि रणनीतिक विफलता का भी संकेत है और यह प्रश्न भी खड़ा करता है कि क्या विपक्ष केवल भाजपा-विरोध के आधार पर टिक सकता है या उसे एक ठोस वैचारिक और नीतिगत आधार की भी आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता केवल सत्तापक्ष की नीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक सजग, विवेकशील और रचनात्मक विपक्ष पर भी उतनी ही आधारित होती है। विपक्ष का मूल दायित्व केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करना, नीतियों की खामियों को तथ्यों के आधार पर उजागर करना और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संसद एवं समाज के समक्ष रखना है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन का संरक्षक होता है। उसे विकास कार्यों में सहयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बना रहे। दुर्भाग्यवश, पिछले दो दशकों में विपक्ष का एक बड़ा वर्ग इस रचनात्मक भूमिका से भटकता दिखाई दिया है, जहां नीतिगत बहसों की जगह व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक शोर-शराबा अधिक प्रमुख हो गया है।

इंडिया गठबंधन का गठन एक बड़े राजनीतिक उद्देश्य के साथ हुआ था-भाजपा के वर्चस्व को चुनौती देना। प्रारंभिक स्तर पर यह प्रयास कुछ हद तक सफल भी दिखाई दिया, जब इस गठबंधन ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से दूर रखने में भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि यह गठबंधन वैचारिक एकता से अधिक राजनीतिक अवसरवाद पर आधारित है। गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका आंतरिक समन्वय है, जहां विभिन्न दलों के अपने-अपने क्षेत्रीय हित, नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं और अलग-अलग राजनीतिक एजेंडे अक्सर एक-दूसरे से टकराते हैं। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के प्रश्न तक, हर स्तर पर मतभेद सामने आते रहे हैं, जिससे यह स्थिति बनती है कि केवल एक साझा विरोध के आधार पर गठबंधन को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। लोकसभा में

विपक्ष के नेता राहुल गांधी और शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी जैसे प्रमुख चेहरों के बीच जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, वह गठबंधन की आंतरिक स्थिति को और अधिक उजागर करती है। सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे की आलोचना करना न केवल राजनीतिक परिपक्वता की कमी को दर्शाता है, बल्कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा करता है। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का तरीका और मंच भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब गठबंधन के नेता ही एक-दूसरे के खिलाफ बयान देने लगें, तो यह संदेश जाता है कि गठबंधन केवल नाम का है और वास्तविकता में वह बिखराव की ओर बढ़ रहा है।

महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष का रुख भी उसकी रणनीतिक कमजोरी को उजागर करता है। यह विधेयक भारतीय समाज की आधी आबादी से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन इसका विरोध जिस रूप में सामने आया, उसने विपक्ष की स्थिति को कमजोर किया। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका स्वरूप रचनात्मक होना चाहिए था। यदि विपक्ष इस विधेयक में सुधार के सुझाव देता, उसके क्रियान्वयन की समय-सीमा और प्रक्रिया पर सवाल उठाता, तो वह अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बन सकता था, लेकिन सीधे विरोध में खड़ा होना, वह भी बिना स्पष्ट जनसंदेश के यह दर्शाता है कि विपक्ष मुद्दों को समझने और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करने में चूक कर रहा है। इसका प्रभाव विशेष रूप से महिला मतदाताओं पर पड़ा, जिन्होंने इसे अपने अधिकारों के विस्तार के रूप में देखा और इसी का राजनीतिक लाभ भाजपा ने अपनी रणनीति के माध्यम से उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मसमीक्षा और सुधार की क्षमता रही है। हार के बाद भी वह अपने संगठन, नेतृत्व और रणनीति में बदलाव करती है, जिससे वह और अधिक मजबूत होकर सामने आती है। इसके विपरीत, विपक्ष अक्सर अपनी हार के कारणों को बाहरी परिस्थितियों में खोजता है, जिससे वह अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में असफल रहता है। राजनीति में परिपक्वता का अर्थ है हार को स्वीकार करना, उससे सीखना और भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाना, लेकिन इस दिशा में विपक्ष को अभी लंबा रास्ता तय करना है।

विपक्षी गठबंधन के भीतर सबसे बड़ा संकट हितों का टकराव है, जहां हर दल अपने क्षेत्रीय आधार को मजबूत करने की कोशिश करता है और इसी प्रक्रिया में वह अपने सहयोगी दलों से भी प्रतिस्पर्धा करने लगता है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक साथ चलते हैं और अंततः यही स्थिति बिखराव को जन्म देती है।

जब तक गठबंधन के भीतर स्पष्ट भूमिका निर्धारण, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और नेतृत्व की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक यह टकराव समाप्त नहीं होगा। विपक्षी दलों की यह नाकामी केवल रणनीतिक कमजोरी नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व की मंशा और प्राथमिकताओं पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। जब विपक्ष जनहित के मुद्दों को छोड़कर सत्ता प्राप्ति के लिए अवसरवादी गठजोड़, भ्रामक प्रचार और व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेता है, तब वह अपनी नैतिक विश्वसनीयता खो देता है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व जनभावनाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व करना और सरकार को सही दिशा में प्रेरित करना है, न कि केवल विरोध के लिए विरोध करना। आज आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष अपने आचरण और दृष्टिकोण में सुधार लाए, सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित राजनीति को पुनर्जीवित करे तथा जनता के विश्वास को पुनः अर्जित करे। तभी भारतीय लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में मजबूत और संतुलित बन सकेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष स्वयं को पुनर्गठित करे, अपनी वैचारिक स्पष्टता स्थापित करे और जनता के सामने एक सकारात्मक एवं ठोस विकल्प प्रस्तुत करे। केवल विरोध की राजनीति अब पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनहित के मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण और व्यवहारिक समाधान भी आवश्यक हैं।

आंतरिक मतभेदों को सार्वजनिक करने के बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाना होगा और जनता के बदलते मिजाज को समझते हुए अपनी रणनीति को नया स्वरूप देना होगा। भारतीय राजनीति एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है, जहां मतदाता अधिक सजग और निर्णायक हो चुका है। ऐसे में गठबंधन की राजनीति को केवल संख्या के खेल से आगे बढ़कर विश्वास, समन्वय और स्पष्टता की नींव पर खड़ा होना होगा। बिखराव केवल राजनीतिक शक्ति को ही कमजोर नहीं करता, बल्कि लोकतंत्र के संतुलन को भी प्रभावित करता है। अंततः राजनीति में वही सफल होता है जो समय के साथ सीखता है, बदलता है और स्वयं को बेहतर बनाता है। हार को पचाना और उससे सीख लेना केवल एक कहावत नहीं, बल्कि सफल राजनीति का मूलमंत्र है, जिसे भाजपा ने बार-बार सिद्ध किया है और अब विपक्ष के सामने भी यही चुनौती है कि वह इस मूलमंत्र को अपनाकर अपने बिखराव को शक्ति में बदल पाए या फिर आंतरिक संघर्षों में उलझकर अपनी प्रासंगिकता खोता जाए।

बांग्लादेशी अवैध प्रवासन की जटिल समस्या का समाधान सिर्फ भाजपा

शेखर अय्यर

असम विधानसभा चुनाव के नतीजों का सीधा श्रेय कांग्रेस के पूर्व नेता और दो बार के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जाता है। अपने नेतृत्व के खास अंदाज और राजनीतिक सूझबूझ के दम पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगातार तीसरी बार जीत दिलाई। इस जीत के साथ सरमा अब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रभावशाली चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। सरमा की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता यह रही कि उन्होंने असम के बहुसंख्यक समाज को यह विश्वास दिलाया कि बांग्लादेश से होने वाले अवैध प्रवासन जैसी पुरानी और जटिल समस्या का समाधान केवल भाजपा ही कर सकती है। वहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। इसी कारण भाजपा ने 2021 के अपने 75 सीटों के आंकड़े को पार करते हुए लगभग 44.51 प्रतिशत वोट हासिल किए। सरमा ने यह सुनिश्चित किया कि जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे। उन्होंने खुद को एक सख्त और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। साथ ही, वह मोदी सरकार के वादों को जमीन पर उतारने में सक्षम रहे। हालांकि, उनके विरोधी उन पर असम में बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त शब्द 'मियां' के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आरोप लगाते रहे। पर, कांग्रेस यह समझने में नाकाम रही कि असम की बहुसंख्यक आबादी लगातार हो रहे प्रवासन को लेकर चिंतित थी। सरमा ने 34 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में हिंदू वोटों को मजबूती से अपने पक्ष में संगठित किया। इसके साथ ही, 2023 के परिसीमन ने भी भाजपा को फायदा पहुंचाया। एक कुशल रणनीतिकार के रूप में सरमा ने समय-समय पर अपने राजनीतिक समीकरण बदले। इसके

अलावा, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ), जो 2021 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'महाजोत' का हिस्सा था, एनडीए के साथ आ गया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा गौरव गोगोई, जो खुद अपनी सीट नहीं बचा सके और 23,000 मतों से हार गए, पर राहुल गांधी ने अधिक भरोसा जताया। नतीजतन, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगे और पार्टी में नाराजगी बढ़ने लगी। कई जगहों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला, जिसने गठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े किए। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आठ दलों के गठबंधन 'महाजोत' का नेतृत्व किया था, जिसने 43.68 प्रतिशत वोट हासिल कर 50 सीटें जीती थीं। इनमें से कांग्रेस ने 29.67 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 29 सीटें अपने नाम की थीं। 2021 में विपक्षी गठबंधन की ताकत दो अहम पार्टियों-बीपीएफ और बदरूद्दीन अजमल की अगुवाई वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ)-से भी बढ़ी थी। पर इस बार तस्वीर बदल गई। बीपीएफ अब एनडीए के साथ है, जबकि एआईयूडीएफ अकेले मैदान में उतरी, क्योंकि कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन करने से साफ इन्कार कर दिया। नतीजों में भी यह असर साफ दिखा।

केरल से सत्ता तो केरलम् से ही हाशिये में जाती कम्युनिस्ट पार्टियां

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

पांच राज्यों के 4 मई के चुनाव परिणाम देश में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आये हैं। एक और जहां पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल का ममता बनर्जी सरकार की करारी हार हुई है तो केरलम् में एलडीएफ की करारी हार के साथ ही देश में एक मात्र वामपंथी सरकार का भी अंत हो गया है। असम में हिमंता सरकार की हेटट्रिक, पुडुचेरी में एनडीए की वापसी और तमिलनाडू में डीएमके-एआईडीएमके की 57 साल की राजनीति का अंत और अभिनेता से नेता बने विजयन का उदय बहुत कुछ कहता है। जनता ने अपना मेंडेट दे दिया है तो चुनाव आयोग ने भी अपना कार्य बखूबी निभा दिया है भले ही अब हारने वाले लाख आरोप-प्रत्यारोप लगायें पर इन चुनावों की एक खास विशेषता यह रही कि मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी और हिंसा भी लगभग नहीं के बराबर रही है। प.बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ भाजपा का वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया है वहीं सबसे अधिक चिंतनीय व गंभीर परिणाम यह रहा है कि केरलम् में वामपंथी सरकार की हार के साथ ही देश में वामपंथ हाशिये में चला गया है। मजे की बात यह है कि 1956 में त्रावणकोर, कोचिन और मालाबार को मिलाकर बने केरलम् की 1957 की पहली चुनी हुई सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूदरीपाद की बनी। ठीक 70 साल बाद केरलम् में वामपंथियों की हार के साथ ही देश में वामपंथियों की एकमात्र राज्य की अंतिम सरकार का भी अंत हो गया है। सवाल यह उठने लगा है कि प. बंगाल और त्रिपुरा की तरह केरलम् में भी क्या अब वामपंथी सरकार आने वाले सालों में वापसी नहीं कर पायेगी ? इतिहास तो यही बता रहा है कि 34 साल के लगातार शासन के बावजूद 2011 के बाद से प. बंगाल में कम्यूनिस्ट सरकार की वापसी नहीं हो पायी है तो 25 साल से सरकार के बावजूद त्रिपुरा में भी 2018 के बाद से कम्युनिस्ट सरकार की वापसी नहीं हो पायी है। इससे लगता है कि वामपंथ या कम्युनिस्ट सरकारें अब इतिहास का हिस्सा बनती जा रही है। मजे की बात यह है कि लोकसभा में भी आज कम्युनिस्टों का प्रतिनिधित्व सिमट कर 4 की संख्या तक

रह गया हैं हांलाकि यह गत लोकसभा से एक ज्यादा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि 1977 के बाद जिस तरह से भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा बढ़ा वह 1990 के दशक में किंग मेकर की स्थिति में आ गया था यहां तक कि 2004 में लोकसभा में 59 सदस्यों के साथ कम्यूनिस्ट पार्टियों की सर्वाधिक भागीदारी रही और ज्योतिबसु को एक बार नहीं अपितु तीन बार देश का प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया पर वामपंथियों में अहम् की लड़ाई के चलते यह अवसर खो दिया और इसके बाद तो कम्यूनिस्ट पार्टियां धीरे धीरे हाशिये में जाती रही जबकि सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष रहे तो उस दौर में कम्यूनिस्ट पार्टियां किंग मेकर की भूमिका निभा रही थी। एक दौर था जब कम्युनिस्ट पार्टियों के बड़े बड़े नाम होते थे। समय ने पलटा खाया और धीरे धीरे पार्टियां पहचान खोने लगी।

हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास आजादी से पहले का है। 26 दिसंबर, 1925 को मानवेन्द्र नाथ रॉय जिन्हें एमएन रॉय के नाम से भी अधिक जाना जाता रहा है ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उस समय अवनी मुखर्जी, एसबी घाटे, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक सिद्धिकी उनके संस्थापक साथी रहे। कम्युनिस्टों की भारतीय राजनीति में उभार को इसी से समझा जा सकता है कि आजादी के बाद 1957 में केरल की पहली चुनी हुई सरकार वामपंथियों की बनी। यह दूसरी बात है कि बाद में कांग्रेस द्वारा इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। पर आजादी के बाद से अब तक केरल में अधिकांश शासन कम्युनिस्ट पार्टियों का ही रहा है। प. बंगाल में भी 1977 से 2011 तक लगातार कम्यूनिस्ट सरकार रही। त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों का बीच बीच में अंतराल के बावजूद काफी समय तक रहा है। माणिक सरकार के बाद से बीजेपी एनडीए गठबंधन ने त्रिपुरा में सत्ता संभाल ली है। 1964 में चीन को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ और भाकपा और माकपा दो पार्टियां बन गई। धीरे धीरे बर्चस्व और अहम् की लड़ाई ने कम्युनिस्ट आंदोलन को धक्का पहुंचाने के बाद ही भारतीय राजनीति में भी कम्यूनिस्ट पार्टियों का प्रभाव कम होता गया।

वैसे उदारीकरण के दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने नए तरह की चुनौतियां सामने आई और 1922 में रुस में बना यूएसएसआर तक 70 साल बाद ही 1991 आते आते बिखराव के दौर में आ गया। यूक्रेन सहित कई राज्य अलग हो गए और आज रुस और यूक्रेन का संघर्ष जगजाहिर है। चीन ने समयानुकूल सोच विकसित किया और आज औद्योगिक दुनिया में चीन का वर्चस्व है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश चीन के वर्चस्व से चिंतित है और चीन की काट देखने लगा है। खैर यह विषयांतर होगा।

सौ टके का सवाल यह है कि केरलम् की विजयन सरकार की हार को देश में वामपंथी सरकारों का अंत माना जाना चाहिए या फिर वापसी की संभावना हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब केन्द्र में वामपंथियों का दखल बढ़ा तो वहीं वामपंथी पार्टियों के बिखराव का कारण बन गया। इगो के चलते ज्योतिबसु का विरोध हुआ तो सोमनाथ चटर्जी तक का विरोध किया गया। दरअसल समय के साथ बदलाव और समय की नब्ज को नहीं पहचानने से ही समस्याएं होती है। आज लगभग यही स्थिति स्थानीय दलों की होती जा रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजनसमाज पार्टी, शिव सेना, एनसीपी, जेडीयू, जेडीएस, आप, शिरोमणी अकाली दल आदि धीरे धीरे जनाधार खोते जा रहे हैं और राज्यों तक ही सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को सोच, नीति और रणनीति में बदलाव लाना होगा नहीं तो भविष्य में रही सही पहचान भी खोने में देरी नहीं लगेगी।

59 वर्ष बाद दो द्रविड़ स्तंभों से बाहर निकली तमिलनाडु की राजनीति

विनोद पाठक

चेन्नई में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और नवोदित तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) पार्टी के संस्थापक जोसेफ विजय चंद्रशेखर के घर उल्लास का माहौल है। परिवार के सदस्यों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो टीवीके के चुनाव चिह्न सीटी को बजा रहे हैं। मात्र दो साल पहले विजय ने टीवीके की स्थापना की थी। नतीजों से स्पष्ट है, वो तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि, राज्य की राजनीति में किसी फिल्मी स्टार का उदय नई बात नहीं है।

वैसे पहले, तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय (1967 से अब तक) तक दो बड़े द्रविड़ स्तंभों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के बीच सीमित रही है। अब जिस तरह अभिनेता से नेता बने विजय राजनीति के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का संकेत है कि राज्य की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह केवल सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं, अपितु मतदाता के मन में गहराते बदलाव का प्रतिबिंब भी है।

द्रविड़ राजनीति की पहचान हमेशा सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी रही है, लेकिन समय के साथ हर विचारधारा को खुद को नए संदर्भों में ढालना पड़ता है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सरकार ने कई योजनाएं लागू कीं, परंतु शासन केवल योजनाओं का विस्तार नहीं होता, वह भरोसे की निरंतरता भी मांगता है। पिछले कुछ समय में बिजली दरों में वृद्धि, संपत्ति कर और शहरी अव्यवस्थाओं जैसे मुद्दों ने आम नागरिक के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। ऐसे छोटे-छोटे असंतोष जब एक साथ जमा होते हैं तो वे सत्ता विरोध की एक मजबूत धारा बन जाते हैं।

द्रमुक के भीतर परिवार के बढ़ते प्रभाव ने भी सवाल खड़े किए। उदयानिधि स्टालिन का तेजी से उभार यह संकेत देता है कि क्या राजनीतिक अवसर समान रूप से वितरित हो रहे हैं या नहीं? राजनीति में विरासत कोई नई

बात नहीं है, लेकिन जब यह योग्यता पर भारी पड़ती दिखे तो जनता का विश्वास डगमगाने लगता है। इसी के समानांतर, धार्मिक मुद्दों पर दिए गए कुछ बयानों ने भी एक बड़े वर्ग को असहज किया है। द्रविड़ राजनीति का मूल स्वर भले ही धर्मनिरपेक्षता रहा हो, लेकिन आज का मतदाता अपनी पहचान के हर पहलू को सम्मान के साथ देखना चाहता है। यदि उसे यह सम्मान नहीं मिलता तो उसकी नाराजगी चुपचाप वोट में बदल जाती है।

ऐसे माहौल में विजय और उनकी पार्टी टीवीके का उभार केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, अपितु सामाजिक मनोविज्ञान का परिणाम है। विजय की लोकप्रियता फिल्मों से शुरू हुई, लेकिन उन्होंने उसे केवल परदे तक सीमित नहीं रखा। उनके प्रशंसक समूह धीरे-धीरे एक संगठित राजनीतिक आधार में बदल गए। यह वही रास्ता है, जिसे कभी एम.जी. रामचंद्रन ने अपनाया था और बाद में वह तमिलनाडु की राजनीति में स्थाई छाप छोड़ गए। फर्क इतना है कि आज का दौर सोशल मीडिया और तेज सूचना प्रवाह का है, जहां छवि और संदेश, दोनों तेजी से बनते और बदलते हैं।

विजय की छवि अपेक्षाकृत साफ-सुथरी रही है। उन्होंने खुद को पारंपरिक द्रविड़ राजनीति और कट्टर वैचारिक ध्रुवों से थोड़ा अलग रखते हुए एक संतुलित विकल्प के रूप में पेश किया है। खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच उनका आकर्षण स्पष्ट दिखता है, लेकिन यहां एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या लोकप्रियता और नैतिक छवि शासन की जटिलताओं को संभालने के लिए पर्याप्त होती है?

इतिहास यह बताता है कि करिश्मा चुनाव जिता सकता है, लेकिन शासन चलाने के लिए अनुभव, टीम और नीतिगत स्पष्टता जरूरी होती है। यदि एआईएडीएम की बात करें तो वो भी धीरे-धीरे अपनी जमीन मजबूत करती दिखाई दे रही है। एडप्पाडी. के. पलनीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी ने आंतरिक संघर्षों को काफी हद तक नियंत्रित किया है। ग्रामीण इलाकों में उसका पारंपरिक आधार अब भी मजबूत है। महंगाई और कृषि संकट जैसे मुद्दों ने उसे फिर से प्रासंगिक बना दिया है। जे. जयाललिता के समय की कल्याणकारी योजनाएं आज भी लोगों के मन में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं।

हालांकि, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। यदि द्रमुक कमजोर होती है तो इंडी गठबंधन की ताकत पर भी असर पड़ेगा। विजय जैसे नए नेताओं का उभार यह संकेत देता है कि भारतीय राजनीति में अब भी नए चेहरों के लिए जगह बनी हुई है, बशर्ते वे जनता की अपेक्षाओं को समझ सकें। दक्षिण भारत, जिसे लंबे समय तक एक स्थिर राजनीतिक क्षेत्र माना जाता था, अब प्रयोग और परिवर्तन का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है।

सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा?, बल्कि यह है कि तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या यह बदलाव केवल अस्थाई लहर है या फिर एक स्थाई परिवर्तन की शुरुआत? क्या द्रविड़ राजनीति अपने मूल स्वरूप को बचाए रखते हुए नए समय के साथ खुद को ढाल पाएगी या फिर नए चेहरे और नए विचार उसे नई दिशा देंगे? तमिलनाडु की जनता अब यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि केवल इतिहास या नाम के आधार पर सत्ता नहीं मिलती। आज का मतदाता परिणाम चाहता है, संतुलन चाहता है और सबसे बढ़कर वह अपने लिए एक ऐसा विकल्प चाहता है, जो उसकी बदलती आकांक्षाओं को समझ सके। यही इस संभावित महापरिवर्तन का सबसे बड़ा संदेश है।

गौरव गोगोई की हार के साथ डूबी कांग्रेस की उम्मीदें

विनोद पाठक

असम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में भाजपा की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। भाजपा की हैट्रिक केवल एक जीत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की रणनीतिक चतुराई का संगम है। चुनावी परिणामों ने विपक्षी खेमे, विशेषकर कांग्रेस के उन तमाम दावों को ध्वस्त कर दिया है, जो बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे थे। इन चुनाव नतीजों का सबसे चौंकाने वाला पहलू कांग्रेस के चेहरा गौरव गोगोई की हार रही है। जोरहाट जैसी प्रतिष्ठित सीट से 23,000 से अधिक वोटों के अंतर से मिली यह हार केवल गौरव गोगोई की व्यक्तिगत हार नहीं है, बल्कि कांग्रेस के उस नैरेटिव की हार है, जो विरासत की राजनीति पर टिका था। गौरव गोगोई, जिन्हें कांग्रेस भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी, अपनी ही जमीन बचाने में विफल रहे। यह परिणाम साबित करता है कि असम की जनता अब केवल नाम या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नहीं, बल्कि डिलीवरी और कनेक्ट पर वोट दे रही है। भाजपा की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे तीन मुख्य कारक रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वोत्तर का विश्वास इस जीत की सबसे बड़ी पूंजी है। केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ और पूर्वोत्तर को मुख्यधारा से जोड़ने के उनके प्रयासों ने भाजपा को हर वर्ग में स्वीकार्य बनाया है। दूसरा, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद को केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि असमिया अस्मिता के रक्षक के रूप में स्थापित किया है। घुसपैठ, सुरक्षा और पहचान जैसे मुद्दों को उन्होंने जिस प्रखरता से उठाया, उसने विपक्ष के पास कोई काट नहीं छोड़ी। तीसरा, अरुणोदय जैसी योजनाओं ने महिलाओं का एक ऐसा साइलेंट वोट बैंक तैयार किया, जिसने बूथों पर जाकर भाजपा के पक्ष में एकतरफा मतदान किया। वहीं, कांग्रेस की इस करारी हार का एक बड़ा कारण राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व की राज्यों से बढ़ती दूरी को माना जा रहा है। जहां भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने असम के हर जिले और मंडल तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहीं राहुल गांधी और दिल्ली का नेतृत्व केवल चुनावी रैलियों तक सीमित रहा। राहुल गांधी की राज्यों की राजनीति में निरंतर सक्रियता की कमी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों के बजाय दिल्ली से तय किए गए नैरेटिव पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, जो असम की जनता को प्रभावित नहीं कर सका। चुनाव प्रचार के दौरान पवन खेड़ा जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं द्वारा हिमंता बिस्वा सरमा पर किए गए तीखे और व्यक्तिगत हमलों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के बजाय नाराज किया। हिमंता ने कुशलतापूर्वक इन हमलों को असम के अपमान से जोड़ दिया, जिससे भाजपा को सहानुभूति का लाभ मिला। चुनावों में भाजपा ने उन मुद्दों को हवा दी, जो सीधे तौर पर जनता की भावनाओं से जुड़े थे। जैसे, अहोम साम्राज्य और शंकरदेव की विरासत को सहेजने का संकल्प भाजपा के पक्ष में गया। ब्रह्मपुत्र पर बनते पुल और सड़कों के जाल ने परिवर्तन को लोगों की आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर दिया। गोगोई पर लगाए गए पाकिस्तान कनेक्शन जैसे आरोपों और कांग्रेस के रक्षात्मक रुख ने विपक्ष की साख को भारी नुकसान पहुंचाया। असम के ये नतीजे यह यही कह रहे हैं कि जीत केवल सोशल मीडिया या टेलीविजन डिबेट से नहीं, बल्कि संगठन की गहराई और स्पष्ट दृष्टि से तय होती है।

इन सब्जियों को भूल से भी कच्चा न खाएं, वरना होगी बड़ी दिक्कत

हम अक्सर हेल्दी रहने के लिए सब्जियों का सेवन बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियों को कच्चा खाने से सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है?

कच्ची सब्जियां अक्सर विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं, लेकिन कुछ में ऐसे रसायन या एंजाइम होते हैं, जो पाचन तंत्र को परेशान कर सकते हैं और पेट की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पाचन से जुड़ी समस्या वाले लोगों के लिए यह और भी जोखिम भरा हो सकता है। किन सब्जियों को कच्चा खाने से बचना चाहिए और इन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे खाया जा सकता है।

ब्रोकली

ब्रोकली विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन कच्ची ब्रोकली में गोइट्रोजन नामक पदार्थ होता है, जो थायरॉयड ग्रंथि पर असर डाल सकता है। इसलिए थायरॉयड की समस्या वाले लोगों को इसे हल्का पकाकर या स्टीम करके खाना चाहिए।

फूलगोभी

फूलगोभी में भी कच्चा खाने पर पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। इसमें गैस पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं, जिससे पेट फूलना और ऐंठन हो सकती है। इसे उबालकर, भूनकर या हल्का स्टीम करना सुरक्षित रहता है।

पत्तागोभी

पत्तागोभी में कच्चा सेवन करने पर भी गैस और पेट में भारीपन की समस्या हो सकती है। इसमें फाइबर तो अधिक होता है, लेकिन कच्चा खाने से पेट पर दबाव बढ़ता है। हल्का उबालकर या स्टीम करके इसका सेवन करना लाभकारी होता है।

टमाटर

कुछ लोगों के लिए कच्चा टमाटर एसिडिटी और पेट दर्द का कारण बन सकता है। इसे हल्का पकाकर या सलाद में सीमित मात्रा में लेना फायदेमंद है।

बैंगन

कच्चा बैंगन हल्का जहरीला होता है। इसमें सोलानिन नामक रसायन मौजूद होता है, जो पेट में जलन, गैस और अपच जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसे हमेशा पकाकर ही खाना चाहिए।

पालक और सरसों का साग

पालक और सरसों के कच्चे पत्तों में ऑक्सलेट्स होते हैं। यह हड्डियों और किडनी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कच्चा सेवन करने से कैल्शियम अवशोषण कम होता है और किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। हल्का पकाकर या स्टीम करके इन्हें खाने से ये सुरक्षित हो जाते हैं।

चाय की छलनी बन सकती है कैंसर की वजह!

चाय हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। सुबह की ताजगी हो या शाम का सुकून, चाय हर किसी की दिनचर्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अक्सर लोग इसके साथ प्रयोग में आने वाले छोटे-छोटे सामानों पर ध्यान नहीं देते।

इनमें से एक है प्लास्टिक की चाय की छलनी, जिसे इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक से निकलने वाले रसायन लंबे समय में शरीर में जमा होकर कैंसर तक का कारण बन सकते हैं।

प्लास्टिक की चाय की छलनी क्यों खतरनाक है और इसके सुरक्षित विकल्प कौन-कौन से हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी चाय को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं।

प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल्स होते हैं हानिकारक

जब आप गर्म पानी या चाय के लिए प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मौजूद BPA और अन्य हानिकारक रसायन चाय में मिल सकते हैं। यह रसायन शरीर में जमा होकर धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए गर्म तरल पदार्थों के साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है।

स्वास्थ्य पर क्या असर दिखेगा

लगातार इन रसायनों का सेवन कैंसर, हार्मोन असंतुलन और प्रजनन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल्स लंबे समय में शरीर की कोशिकाओं और अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं

प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण चाय में घुलकर पेट और आंतों में सूजन, गैस या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यह लंबे समय में पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है।

सुरक्षित विकल्प क्या है?

अगर आप अपनी सेहत के लिए चिंतित हैं तो चाय के लिए हमेशा स्टील, तांबे, सिरेमिक या बांस की छलनी का उपयोग करना चाहिए। ये विकल्प न केवल स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं बल्कि लंबे समय तक टिकते हैं और उपयोग में भी आसान हैं।

पुडुचेरी कैसे जाएं? ट्रेन, फ्लाइट और रोड ट्रिप की पूरी जानकारी

भागती सड़कों और जिंदगी की दौड़भाग से दूर अगर आप शांति की तलाश चाहते हैं तो पुडुचेरी जा सकते हैं। पुडुचेरी भारत का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां फ्रेंच वास्तुकला, नीले समुद्र और धीमी जीवनशैली के बीच सुकून वक्त बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार पुडुचेरी जा रहे हैं तो कई सवाल आपके मन में होंगे, जैसे कैसे यात्रा करें, पुडुचेरी घूमने में कितना समय लगेगा और जेब पर खर्च का भार कितना पड़ेगा?

इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिल सकते हैं। नई दिल्ली से पुडुचेरी के सफर की शुरुआत कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग में से कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए। घूमने के लिए कितने दिन की छुट्टी चाहिए।

दिल्ली से पुडुचेरी की दूरी

नई दिल्ली से पुडुचेरी का सफर करीब 2300 किलोमीटर लंबा है। सफर के लिए कोई आसमान का रास्ता चुनता है, कोई रेल की खिड़की से बदलते भारत को देखना चाहता है, तो कोई सड़क के रोमांच में खो जाना चाहता है। आप जानिए कि कितने बजट में आप कैसे जा सकते हैं।

दिल्ली से पुडुचेरी कैसे जाएं?

फ्लाइट

दिल्ली से पुडुचेरी के लिए हवाई मार्ग का सफर 4- 6 घंटे में तय किया जा सकता है। सीधे पुडुचेरी के लिए फ्लाइट कम मिलती हैं, इसलिए आपको चेन्नई उतरना होगा, जो यहां से पुडुचेरी लगभग 150 किमी दूर है।

दिल्ली से चेन्नई फ्लाइट का सफर लगभग 3-4 घंटे का है। आगे चेन्नई से पुडुचेरी के लिए टैक्सी या बस से सफर करें, जिसमें 3-4 घंटे लग सकते हैं। इसमें लगभग 6,000 से 15,000 रुपये तक फ्लाइट टिकट और कैब पर खर्च हो सकता है। अगर आपके पास समय कम हो तो यही सबसे समझदारी भरा विकल्प है।

ट्रेन

नई दिल्ली से पुडुचेरी की यात्रा रेल मार्ग से भी संभव है ,जिसका सफर 36 से 40 घंटे का हो सकता है। अगर आप यात्रा को महसूस करना चाहते हैं, तो ट्रेन सबसे बेहतर है। सफर लंबा जरूर है मगर भारत की असली तस्वीर यही दिखाता है। दिल्ली से चेन्नई रेलवे स्टेशन या विलुप्पुरम रेवले स्टेशन तक ट्रेन से जाएं। वहां से बस या टैक्सी द्वारा पुडुचेरी पहुंचें। सफर में कुल खर्च 800 रुपये से लेकर 3500 रुपये आ सकता है।

सड़क मार्ग

पुडुचेरी तक रोड ट्रिप भी संभव है। दिल्ली से पुडुचेरी रोड ट्रिप दिल वालों के लिए है। लगभग 2300 किमी का सफर तय करने में 40–45 घंटे का समय लग सकता है और खर्च फ्यूल और टोल मिलाकर 8,000 से 15,000 रुपये तक आ सकता है।

पुडुचेरी जाने का सही समय

पुडुचेरी घूमना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि इस समय वहां सबसे बेहतरीन मौसम देखने को मिलता है। हालांकि अप्रैल से जून तक गर्मी ज्यादा रहती है। वहीं जुलाई से सितंबर के बीच बारिश रहती है लेकिन हरियाली शानदार हो जाती है। ठंडी हवा, समुद्र की नमी और फ्रेंच गलियों का असली जादू सर्दियों में ही दिखता है।

पुडुचेरी ट्रिप का कुल खर्च

अगर आप 3 से 4 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और बजट यात्रा चाहते हैं तो लगभग 8000 रुपये से 12000 रुपये तक खर्च आ सकता है। लग्जरी सफर में 30000 रुपये से ज्यादा प्रति व्यक्ति खर्च आएगा। खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप ठहरते कहां हैं और घूमते कैसे हैं।

पुडुचेरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल

आध्यात्मिक स्थल की सैर चाहते हैं तो अरबिंदो आश्रम और आरोविले में मैट्रिमांडिर जाएं।

पुडुचेरी का पैराडाइज बीच, प्रोमेनेड बीच और आरो बीच पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

फ्रेंच विरासत की सैर के लिए वार मेमोरियल और व्हाइट टाउन जरूर जाएं।

यहां का मुख्य आकर्षण पुडुचेरी लाइट हाउस, बॉटनिकल गार्डन और भारती पार्क है।

फ्रिज में सूख जाते हैं नींबू-धनिया? अपनाएं ये आसान टिप्स, रहेंगे ताजा

गर्मियों में नींबू और धनिया का इस्तेमाल रोजाना होता है। ये दोनों चीजें खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि फ्रिज में रखने के बावजूद नींबू सूख जाते हैं और धनिया मुरझा जाता है। इससे खाने का स्वाद भी प्रभावित होता है और ताजे नींबू -धनिया के लिए बार-बार बाजार भी जाना पड़ता है।

नींबू और धनिया को रखने के सही तरीके के बारे में जानकर आप लंबे समय तक इन्हें ताजा बनाए रख सकते हैं। लोगों का सवाल होता है कि फ्रिज में रखने के बाद भी नींबू और धनिया सूख कैसे जाते हैं? इसका कारण है कि कई लोग नींबू और धनिया को सीधे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे उनमें नमी खत्म होने लगती है और वे जल्दी खराब हो जाते हैं।

अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान किचन टिप्स अपनाकर इन चीजों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

फ्रिज में स्टोर करने का सही तरीका

नींबू को एयरटाइट कंटेनर में रखें

नींबू को खुला रखने से उसकी नमी जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए इसे एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग में स्टोर करें। इससे नींबू कई दिनों तक रसदार और ताजा बना रहता है।

धनिया को पेपर टॉवल में लपेटें

धनिया को धोकर सीधे फ्रिज में

रखने से वह जल्दी सड़ जाता है। इसे पहले अच्छी तरह सुखाएं और फिर पेपर टॉवल में लपेटकर एयरटाइट बॉक्स में रखें। इससे उसकी ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है।

पानी का सही इस्तेमाल करें

धनिया को ताजा रखने के लिए आप उसे एक गिलास पानी में भी रख सकते हैं, जैसे फूलों को रखते हैं। ऊपर से हल्का प्लास्टिक कवर डाल दें और फ्रिज में रखें। यह तरीका भी काफी असरदार है।

फ्रिज का सही तापमान रखें

बहुत ज्यादा ठंडा तापमान भी नींबू और धनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रिज का तापमान मध्यम रखें, ताकि उनकी नमी और ताजगी बनी रहे।

जरूरत के हिसाब से ही धोएं

नींबू और धनिया को स्टोर करने से पहले बार-बार धोने से उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। बेहतर है कि इस्तेमाल से पहले ही इन्हें धोएं, ताकि वे ज्यादा समय तक ताजा रहें।

बिना फ्रिज के कैसे करें स्टोर?

पानी के गिलास का उपयोग

धनिया की जड़ों को थोड़े से पानी से भरे गिलास या जार में रखें, जैसे फूलों को गुलदस्ते में रखा जाता है। यह पत्तियों को हाइड्रेटेड रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस विधि से धनिया काफी समय तक ताजा रहता है।

गीले सूती कपड़े में लपेटना

धनिया को साफ करके एक हल्के गीले सूती या मलमल के कपड़े में लपेटकर किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे उसे जरूरी नमी मिलती रहती है।

मटके का इस्तेमाल

गांव का यह पारंपरिक तरीका बहुत कारगर है। धनिया को कपड़े में लपेटकर खाली मटके या मिट्टी के बर्तन के अंदर रखें और ढक्कन बंद कर दें। मिट्टी की प्राकृतिक ठंडक इसे मुरझाने नहीं देती।

तेल की कोटिंग

नींबू पर हल्का सा नारियल या कुकिंग ऑयल लगाकर उन्हें किसी हवादार टोकरी में रखें। तेल की परत छिलके से नमी को बाहर निकलने से रोकती है।

कागज में लपेटना

प्रत्येक नींबू को अलग-अलग अखबार या पेपर टॉवल में लपेटकर किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें। इससे वे जल्दी पीले होकर नहीं सूखते।

पानी में डुबोकर रखना

एक कांच के जार में पानी भरें और उसमें नींबू डालकर ढक्कन बंद कर दें। पानी को हर दूसरे दिन बदलते रहें। इस तरह नींबू हफ्तों तक रसीले बने रहते हैं।

40 की उम्र के बाद कमजोर होने लगती हैं महिलाओं की हड्डियां, रखें इन बातों का ध्यान

40 की उम्र के बाद महिलाओं में हड्डियों की मजबूती धीरे-धीरे कम होने लगती है। यह मुख्य रूप से हॉर्मोनल बदलाव, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, और जीवनशैली से जुड़ी आदतों के कारण होता है।

कमजोर हड्डियों की समस्या को नजरअंदाज करना भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द और फ्रैक्चर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए इस उम्र में महिलाओं को अपनी डाइट, एक्सरसाइज और जीवनशैली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सही पोषण, नियमित व्यायाम और हड्डियों को मजबूत रखने वाली आदतें अपनाकर महिलाएं इस समस्या से बच सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रख सकती हैं।

सही पोषण

40 के बाद हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए सही आहार बहुत जरूरी है।

कैल्शियम हड्डियों का मुख्य हिस्सा है और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है।

आहार में दूध, दही, पनीर और घी शामिल करें।

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग भी कैल्शियम से भरपूर होती हैं।

अंडे और मछली जैसे सैल्मन विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत हैं।

बादाम, काजू, तिल और अलसी के बीज हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

व्यायाम करें

हड्डियों की मजबूती के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है।

वॉकिंग और जॉगिंग जैसी वेट-बियरिंग एक्सरसाइज हड्डियों को मजबूत करती हैं।

योग और स्ट्रेचिंग संतुलन बढ़ाने और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है।

हल्के डम्बल्स, रेजिस्टेंस बैंड या बॉडीवेट एक्सरसाइज से हड्डियों की घनता बढ़ती है।

धूम्रपान और शराब

धूम्रपान हड्डियों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ाता है।

शराब का अत्यधिक सेवन कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है और हड्डियों की कमजोरी बढ़ा सकता है।

सूरज की रोशनी है जरूरी

विटामिन डी के लिए रोजाना 15-20 मिनट धूप में रहना जरूरी है।

यह हड्डियों में कैल्शियम के सही अवशोषण में मदद करता है।

सुबह या शाम के हल्के समय में बाहर टहलना सबसे सुरक्षित होता है।

हड्डियों की जांच

40 के बाद समय-समय पर बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना जरूरी है।

यह हड्डियों की ताकत और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम का पता लगाने में मदद करता है।

टेस्ट के आधार पर डॉक्टर सप्लीमेंट्स और जीवनशैली में बदलाव की सलाह दे सकते हैं

इस एक चीज की वजह से खतरे में है आपका दिल और किडनी!

आज की तेज-तर्रार लाइफस्टाइल की वजह से लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। काम का तनाव, सही समय पर भोजन न करना और जंक फूड का बढ़ता सेवन, शरीर को कमजोर कर देता है। कई मामलों में, हार्ट की किसी न किसी समस्या ने लोगों को परेशान किया है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने खाने में केवल एक चीज की मात्रा को नियंत्रित करके आप कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं? यह चीज है नमक। अत्यधिक नमक का सेवन आपके रक्तचाप, दिल और किडनी पर सीधा असर डाल सकता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों के अनुसार, रोज़ाना नमक की सही मात्रा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।

ज्यादा नमक का असर

अत्यधिक नमक का सेवन सीधे आपके रक्तचाप पर असर डालता है। जब शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, तो रक्त वाहिकाओं में दबाव बढ़ता है,

जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप रहने से दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक और दिल की अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, शरीर में पानी का अति संचय होने से स्ट्रोक और सूजन जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं।

किडनी पर प्रभाव

किडनी शरीर से अतिरिक्त सोडियम और टॉक्सिन्स निकालने का काम करती हैं। जब आप अधिक नमक खाते हैं, तो किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे गुर्दे धीरे-धीरे कमजोर हो सकते हैं और उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। समय रहते अगर सावधानी न बरती जाए, तो किडनी फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बन सकता है।

कम नमक भी है खतरनाक

नमक की अत्यधिक कमी भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। शरीर में सोडियम की कमी होने पर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन पैदा होता है, जिससे थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है और लंबे समय तक यह हार्मोनल और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकता है।

तो क्या करें?

रोज़ाना 5 ग्राम से अधिक नमक न लें।

पैकेज्ड और जंक फूड में नमक बहुत ज्यादा होता है।

खाना पकाते समय हर्ब्स, मसाले और नींबू का इस्तेमाल करें, ताकि स्वाद के लिए नमक कम करना आसान हो।

शरीर में सोडियम का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है।

हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फंक्शन की नियमित जांच कराएं।

एक बार किसी डाइटिशियन से बात अवश्य करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बिहार सरकार में 32 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

पटना। बिहार में गुरुवार को सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हो गया। राजधानी पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार समारोह का आयोजन किया गया।

जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी समारोह में शामिल हुए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिनों के बाद उनकी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। कैबिनेट विस्तार में भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोजपा रामविलास के दो, हम और आरएलएम के एक-एक नेता ने मंत्रीपद की शपथ ली। सबसे पहले श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जयसवाल, निशांत कुमार और लेशी सिंह ने शपथ ली। दूसरी बार में राम कृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने शपथ ली। इसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, डॉ. संतोष कुमार सुमन और रमा निषाद ने पटना में बिहार मंत्री के रूप में शपथ ली।

118 विधायक लाओ, तभी होगी शपथ : राज्यपाल राजेंद्र

चेन्नई। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। टीवीके प्रमुख विजय गुरुवार को एक बार फिर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होने भर से सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल अपने रुख पर कायम हैं कि विजय को पहले विधानसभा में बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा दिखाना होगा। राजभवन का मानना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में अस्थिर सरकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसलिए 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित करना अनिवार्य होगा। दरअसल, 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। हालांकि विजय खुद दो सीटों से चुनाव जीते हैं और नियमों के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी।

राज्यपाल मौका दें, फ्लोर टेस्ट में साबित करूंगा बहुमत

चेन्नई। अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार सुबह आर. वी. अर्लेकर से मुलाकात की। यह मुलाकात राजभवन को यह समझाने का एक नया प्रयास था कि तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने के लिए तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को आवश्यक समर्थन प्राप्त है। यह मुलाकात विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच हुई है, जिसमें खंडित जनादेश मिला है और टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 234 सदस्यीय सदन में उसे बहुमत नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार, विजय ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है तो वे विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि यदि राज्यपाल उनके नए दावे पर विचार करने से इनकार करते हैं तो पार्टी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

केरल में कौन होगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री?

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनावों में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की महत्वपूर्ण जीत के बाद कांग्रेस नेताओं और एआईसीसी पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे, ताकि कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में भाग ले सकें। पहुँचने पर अजय माकन ने पत्रकारों से कहा कि हम यहाँ मुख्यमंत्री पद की बैठक में शामिल होने आए हैं। देखते हैं कि विधायक क्या चाहते हैं। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यूडीएफ के नेतृत्व वाली पार्टी को निर्णायक जनादेश मिलने के बाद कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन के लिए विचार-विमर्श शुरू कर रहा है। इससे पहले दिन में, केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनमें वी.डी. सतीशन, के. सुरेश और दीपा दासमुंशी शामिल थे, दो पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए तिरुवनंतपुरम के एक होटल में एकत्रित हुए।

असम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 को होगा

गुवाहाटी। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए असम के पुलिस महानिदेशक के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी नव निर्वाचित मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए असम आ रहे हैं। यह समारोह 12 मई को गुवाहाटी के खानापारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में आयोजित किया जाएगा। एक्स पर जारी एक बयान में मुख्य सचिव ने कहा कि यह समारोह 12 मई को खानपारा स्थित पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और इसमें कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उद्योग जगत के विशिष्ट प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आयोजन स्थल की तैयारियों, प्रोटोकॉल और अंतर-विभागीय समन्वय से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों की सराहना की

आतंकवाद को पालने वाले तंत्र को नष्ट करने के लिए भारत आज भी अडिग : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख को दोहराया। पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत न केवल आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उसे पोषित करने वाले पूरे तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प पर आज भी अडिग है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैन्य और आतंकी ढांचे के खिलाफ सैन्य अभियान के एक वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल बाद भी भारत आतंकवाद को हराने और उसे पोषित करने वाले तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प में पहले की तरह ही अडिग है।

पीएम मोदी ने कहा कि एक साल पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेजोड़ साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिमाकत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरा देश भारतीय बलों के शौर्य को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसने हमारे सशस्त्र बलों के पेशेवर रवैये, तैयारी और समन्वित शक्ति को उजागर किया।''

पीएम मोदी ने कहा कि साथ ही इस अभियान ने भारतीय सुरक्षा बलों के बीच बढ़ती एकजुटता को प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किए गए प्रयासों से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को

रेखांकित किया। ऑपरेशन सिंदूर को तीनों रक्षा बलों द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ पश्चिमी सीमा पर सात से 10 मई, 2025 तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए अंजाम दिया गया था। यह अभियान 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे।

गृह मंत्री ने आतंकियों को दी चेतावनी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान भारत की सैन्य शक्ति का ऐतिहासिक प्रतीक बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमेशा दुश्मनों को भारतीय सेना की अचूक मारक क्षमता की याद दिलाता रहेगा।

अमित शाह ने कहा कि इतिहास इस दिन को भारतीय सेनाओं की सटीक स्ट्राइक क्षमता, खुफिया एजेंसियों की सूक्ष्म जानकारी और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के संयुक्त प्रदर्शन के रूप में याद रखेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों और उनके ठिकानों को सीमा पार जाकर नष्ट किया गया।

गृह मंत्री ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे कहीं भी छिप जाएं, भारत की नजर और सेना की मारक शक्ति से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि यह दिन दुश्मनों के लिए हमेशा एक कड़ा संदेश बना रहेगा। अमित शाह ने इस मौके पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और बलिदान को भी सलाम किया।

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि भारत की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग नहीं पड़ा, जैसा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद हुआ था। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इसके उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसीम मुनीर का गर्मजोशी से स्वागत किया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने वाले युद्धविराम की पहली घोषणा 10 मई 2025 को शाम 5:37 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की थी। उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप से यह संभव हुआ। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने बाद में भी कई बार इस दावे को दोहराया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इसका खंडन नहीं किया।

एमके स्टालिन ने तोड़ी चुप्पी, कहा-

एआईएडीएमके से गठबंधन नहीं होगा

चेन्नई। तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डीएमके राज्य में टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय द्वारा नई सरकार बनाने का इंतजार करने को तैयार है और उन्होंने आगे कहा कि वे छह महीने तक बिना किसी हस्तक्षेप के स्थिति पर नजर रखेंगे। इस बयान के साथ, स्टालिन ने एआईएडीएमके और डीएमके के गठबंधन की संभावना को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

डीएमके की ओर से संकेत देते हुए कि वह राज्य में संवैधानिक संकट या जल्द ही एक और चुनाव नहीं चाहती, स्टालिन ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को जारी रखेगी, साथ ही तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को भी पूरा करेगी। अपनी प्राथमिकता सूची के बारे में पूछे जाने पर स्टालिन ने कहा कि नई सरकार को स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना जारी रखनी चाहिए।

स्टालिन ने कहा कि और 'कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' (परिवार की महिला मुखियाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता)। विजय द्वारा

महिलाओं को 2,500 रुपये देने के वादे के बारे में बात करते हुए, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वादे को निभाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम 1,000 रुपये तो दें, जैसा हमने दिया। डीएमके अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 2021 के घोषणापत्र में किए गए 90त्न वादे पूरे किए हैं और कहा कि कुछ वादे, जैसे कि हृश्वश्वज्ञ को बंद करना, केंद्र के नियंत्रण में होने के कारण पूरे नहीं किए जा सके। स्टालिन ने कहा कि इस चुनाव में भी, हमने केवल उन्हीं चीजों का वादा किया जिन्हें हम पूरा कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि टीवीके अपने वादे (राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर) पूरे कर पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे ऐसा कर दें तो हमें खुशी होगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन बहुमत के लिए उसे 10 सीटों की कमी रह गई।

भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर कोलकाता पुलिस अलर्ट

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 4000 जवान तैनात

कोलकाता। कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए करीब 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली सरकार का शपथग्रहण समारोह नौ मई को यहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस मैदान को प्रभावी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए लगभग 30 सेक्टरों में विभाजित किया गया है।

उन्होंने बताया कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड और आसपास के इलाकों में करीब 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक सेक्टर की निगरानी पुलिस उपायुक्त या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। अधिकारी ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भी तैनाती की जा सकती है। कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार में वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक कर इस कार्यक्रम की सुरक्षा रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। समारोह में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। प्रवेश द्वारों पर डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंडहेल्ड स्कैनर लगाए जाएंगे, जबकि पूरे स्थल की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी।

अधिकारी ने कहा, ''हम यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम कर रहे हैं कि मैदान के भीतर कोई प्रतिबंधित या खतरनाक वस्तु न लाई जा सके। आसपास की इमारतों की छतों से भी निगरानी की जाएगी।'' पुलिस ने बताया कि यातायात जाम से बचने के लिए शनिवार को इलाके में यातायात प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं और मार्ग परिवर्तन भी किया जा सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

दिल्ली कैपिल्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे अभी बंद नहीं

नई दिल्ली। आईपीएल के इस 19 वें सत्र में अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और उसे 10 में से 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। जिससे उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनएं भी कमजोर हुई हैं हालांकि ये समाप्त नहीं हुई हैं। कैपिटल्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। टीम 6 हारने के बाद वे अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गयी है। टीम के अभी आठ अंक हैं और उसे अब बचे हुए सभी चार मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे।

उसे प्लेऑफ में पहुंचने इन सभी चारों मैचों में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। ऐसा करने पर उनके अंकों की संख्या बढ़कर 16 पहुंच जाएगी। आईपीएल इतिहास पर ध्यान दें तो 16 अंकों वाली टीम को प्लेऑफ में अवसर मिल ही जाता है। उसे पर , अपने नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा, जो वर्तमान में माइनस में है और करीबी मुकाबलों में निर्णायक साबित हो सकता है।

दिल्ली कैपिटल्स को अब हर मैच जीतना होगा। एक भी हार उसे बाहर कर देगी। यदि वे बचे हुए चार मैचों में से एक भी मुकाबला हारते हैं, तो उनके अधिकतम अंक 14 तक ही पहुंच पाएंगे। इस बार 14 अंकों के साथ प्लेऑ में पहुंचना लगभग असंभव है। अंक तालिका की स्थिति देखें तो पाएंगे कि पहले से ही छह टीमों के खाते में 10 या उससे अधिक अंक हैं। इनमें से एक टीम के पास 13 अंक हैं और चार टीमें 12-12 अंकों के साथ शीर्ष-4 में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में 14 अंक पर टीम बाहर हो जाएगी। अधिकतर टीमें 16 या उससे अधिक अंक तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली के लिए राह और भी कठिन इस कारण से है क्योंकि उनके बाकी बचे चार मुकाबले आसान नहीं हैं। उन्हें दो बार कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से खेलना है। इसके अलावा उसे पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स से भी खेलना है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 114 अंक टूटा निफ्टी 24,300 के पार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को पूरे कारोबारी सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 381 अंक की बढ़त लेकर 78,339.24 पर खुला। लेकिन अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सका। दिन के कारोबार के दौरान इस इंडेक्स ने 78,384.70 के हाई और 77,713.21 के लो रेंज में ट्रेड किया। अंत में सेंसेक्स 114 अंक यानी 0.15% की गिरावट लेकर 77,844.52 पर बंद हुआ। इसी तरह, 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी-50 24,398.50 पर खुला। दिन के कारोबार के दौरान इस इंडेक्स ने 24,482.10 के हाई और 24,284.00 के लो रेंज में ट्रेड किया। अंत में निफ्टी-50 4.40 अंक यानी 0.02% फिसलकर 24,326.65 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं।

भारत की स्पेस कंपनी स्काईरूट बनी यूनिकॉर्न

नईदिल्ली। भारत की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस लॉन्च कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने गुरुवार को लगभग 60 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की घोषणा की। इस फंडिंग के बाद कंपनी का प्री-मनी वैल्यूएशन 1.1 अरब डॉलर पहुंच गया है और इसके साथ ही कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है। इस फंडिंग राउंड की अगुवाई शेरपालो वेंचर्स और वैश्विक संस्थागत निवेशक जीआईसी ने संयुक्त रूप से किया। इसमें स्काईरूट के मौजूदा निवेशकों ने भी भाग लिया, जिनमें ग्रीनको ग्रुप के संस्थापक और अरकम वेंचर्स शामिल हैं। शेरपालो के संस्थापक, प्रसिद्ध टेक निवेशक और अल्फाबेट इंक के बोर्ड सदस्य राम श्रीराम अब स्काईरूट के बोर्ड में शामिल होंगे। नई फंडिंग से यह साफ है कि निवेशकों को स्काईरूट के दुनिया की प्रमुख स्पेस लॉन्च सर्विस कंपनियों में शामिल होने की क्षमता पर मजबूत भरोसा है।

भारत फोर्ज का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 17 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली। रक्षा उपकरण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 17 प्रतिशत घटकर 233.45 करोड़ रुपए रहा। कंपनी को 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में 282.62 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। भारत फोर्ज ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय बढ़कर 4,528.04 करोड़ रुपए हो गई जो एक वर्ष पहले समान तिमाही में 3,852.6 करोड़ रुपए थी। इस दौरान कुल खर्च 3,483.04 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,089.33 करोड़ रुपए हो गया। भारत फोर्ज ने कहा कि चौथी तिमाही में उसे कुल 98.73 करोड़ रुपए का असाधारण खर्च वहन करना पड़ा जिसमें अनुषंगी कंपनी में निवेश में कमी, श्रम संहिता का प्रभाव एवं उसकी जर्मन इकाई भारत फोर्ज सीडीपी जीएमबीएच के पुनर्गठन से जुड़े आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

हिंदुस्तान जिंक के शेयर ने 1 लाख के बनाए 14 करोड़

नईदिल्ली। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां निवेशकों की सूझ-बूझ से ही नहीं बल्कि किस्मत के साथ की भी जरूरत होती है। ऐसे कई शेयर है जहां समय से अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो किस्मत पलट सकती है। ऐसा ही एक शेयर जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसने पिछले दो दशकों से ज्यादा समय में अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर करोड़पति और अरबपति तक बना दिया है। यह कहानी साल 2002 से शुरू होती है, जब इस कंपनी में निवेश करने का मौका मिला। अगर किसी निवेशक ने उस समय सिर्फ 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 14 करोड़ रुपये तक पहुंच गई होती। यह रिटर्न लगभग 1400 गुना माना जा रहा है, जो इसे भारत के बड़े मल्टीबैगर शेयरों में शामिल करता है।

पारंपरिक व्यापार की रीढ़ है स्थानीय फुटकर विक्रेताओं का नेटवर्क

मनीष शर्मा

फूड इंडस्ट्री में कई साल काम करने के बाद मैंने यह समझा है कि भले ही तेजी से मॉडर्न सिस्टम आ गए हों, लेकिन आज भी जनरल ट्रेड ही डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण प्रणाली की रीढ़ है। मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स ब्रांड को दिखाने में मदद करते हैं, लेकिन असली पहुंच जनरल ट्रेड से ही बनती है, खासकर दूर-दराज के इलाकों में। यहां पर्सनल कस्टमर सर्विस और उधार पर बिक्री जैसी पारंपरिक तरीके आज भी बहुत मायने रखती हैं।

मेरे अनुभव में जनरल ट्रेड एक सरल लेकिन मजबूत स्ट्रक्चर पर चलता है। सबसे पहले कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, जो स्टॉक और लॉजिस्टिक्स संभालते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, जो मार्केट में काम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ बीच का आदमी नहीं होता, बल्कि अपने एरिया में ब्रांड का चेहरा भी होता है। वह रिटेलर्स से रिश्ते बनाकर और उत्पाद को आगे बढ़ाकर सीधे बिजनेस पर असर डालता है। एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मुश्किल समय में भी ग्रोथ बनाए रख सकता है। मैंने यह भी सीखा है कि सही डिस्ट्रीब्यूटर चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसकी फाइनेंशियल स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस में उसकी भागीदारी और आगे बढ़ने की सोच को समझना जरूरी होता है। इसके साथ ही इन रिश्तों को अच्छे से मैनेज करना भी जरूरी है। नियमित बातचीत, सही टारगेट, मोटिवेशन और सही इंसेंटिव से ही अच्छा तालमेल बनता है।

इसके बाद आती है सेल्स टीम, जो जमीन पर काम करती है और असली परिणाम देती है। ऑफिस में बैठकर आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लें, अगर

आपकी सेल्स टीम सही तरीके से बनी और मैनेज नहीं है, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही टेरिटरी प्लानिंग से समय बचता है और काम बेहतर होता है। जब एरिया संभालने लायक होता है, तो सेल्स टीम अच्छे रिश्ते बना पाती है, काम में लगातार सुधार आता है और बिक्री बढ़ती है। अच्छा काम करने पर रिवार्ड और पहचान देने से टीम का मनोबल और काम करने की क्षमता दोनों बढ़ती हैं।

मैं हमेशा मानता हूं कि मार्केट में काम करने का तरीका (रूट टू मार्केट) लचीला होना चाहिए। हर मार्केट अलग होता है, इसलिए एक ही तरीका हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। सफलता इस बात में है कि आप बदलाव के अनुसार खुद को ढालें। आखिर में सबसे जरूरी चीज है कि आपका प्रोडक्ट हर जगह उपलब्ध हो और जब ग्राहक को जरूरत हो, तब उसे मिल जाए। रिटेल में काम करते समय प्राथमिकता तय करना जरूरी है। बड़े आउटलेट ज्यादा बिक्री देते हैं, लेकिन ज्यादा जगहों पर मौजूदगी से ब्रांड की पहचान और उपलब्धता दोनों बढ़ती हैं। सही बैलेंस बनाने से ही ग्रोथ मिलती है। प्राइसिंग भी बहुत जरूरी है। पूरी चेन में हर किसी को सही मुनाफा मिलना चाहिए- चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो या कंपनी। अगर किसी को फायदा नहीं मिलेगा, तो वह आपके प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो। इसी तरह उधार देना जरूरी है, लेकिन उसका सही कंट्रोल भी होना चाहिए, जैसे लिमिट तय करना और समय पर पैसे वसूलना। पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव सेकेंडरी सेल्स को ट्रैक करने में आया है। पहले फैसले अंदाजे पर होते थे, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सिस्टम से काफी पारदर्शिता आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रिटेल तक कैसे जा रहा है, कहां कमी है और जल्दी सुधार कर सकते हैं। इससे काम ज्यादा प्रभावी हो गया है, जबकि मानवीय संबंध भी बने रहते हैं। ट्रेड स्कीम और प्रमोशन आज भी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से चलाना चाहिए। एक अच्छी स्कीम पूरे चैनल में ऊर्जा भर सकती है, जबकि खराब स्कीम कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। फोकस हमेशा असली बिक्री बढ़ाने पर होना चाहिए, सिर्फ स्टॉक आगे धकेलने पर नहीं। इसके साथ ही दुकान के अंदर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी यानी वस्तु का दिखना भी ग्राहक के फैसले को प्रभावित करती है।

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने वाली जनहितैषी पहल

बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लागू

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लागू की गई है। यह योजना घरेलू, बीपीएल एवं कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के भुगतान में राहत देने के साथ-साथ आसान समाधान उपलब्ध करा रही है।

योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का भुगतान एकमुश्त अथवा आसान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। विशेष बात यह है कि 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिलों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी उपभोक्ता आर्थिक कारणों से बिजली सुविधा से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ योजना को सरल और सुलभ बनाया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं का पंजीयन अनिवार्य रखा गया है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पंजीयन की व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ता मोर बिजली एप, सीएसपीडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट, नजदीकी बिजली कार्यालय तथा विशेष पंजीयन शिविरों के माध्यम से आसानी से अपना पंजीयन करा सकते हैं। यह योजना 12 मार्च 2026 से लागू है तथा योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। अब तक लाखों उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं और बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण कर उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपए की राहत प्रदान की जा चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक प्रदेश के 07 लाख 24 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया है। 1 लाख 63 हजार प्रकरणों का निराकरण कर कुल 06 करोड़ 22 लाख रूपये से अधिक की राहत प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और आम नागरिकों को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 इसी जनहितकारी सोच का परिणाम है, जो लाखों उपभोक्ताओं के जीवन में राहत और विश्वास लेकर आई है।

यातायात नियमों के पालन में ही जीवन की सुरक्षाः टीके भोई

नवा रायपुर। ब्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर-20 के शान्ति शिखर में आयोजित समर कैम्प में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए यातायात प्रशिक्षक टी. के. भोई ने कहा कि हमें यातायात के सारे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए क्योंकि यह हमारी ही जीवन रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कभी भी शार्ट कट के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए।

उन्होंने बतलाया कि हमारे देश में लोगों की मृत्यु का पांचवा सबसे बड़ा कारण सडक़ दुर्घटना है। मरने वालों में अस्सी प्रतिशत संख्या युवाओं की होती है जो कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि रायपुर में हर महिने हजारों की संख्या में नई गाडियाँ पंजीकृत होती हैं। किन्तु सडक़ों की संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में सडक़ों पर चलने के लिए जगह नहीं बचेगी।

उन्होंने बतलाया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं चालक की लापरवाही से होती है। यदि चालक अच्छा हो और वह यातायात नियमों का पालन करता हो तो दुर्घटनाओं की सम्भावना कम हो जाती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात संकेतों का भी ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने विस्तार से बच्चों को चित्रों के माध्यम से यातायात संकेतों का परिचय दिया तथा उनका पालन करने की नसीहत दी। उन्होंने बतलाया कि यह संकेत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में एक समान होते हैं। उन्होंने कहा कि सडक़ पार करने के लिए जेब्रा कासिंग का ही उपयोग करना चाहिए। सडक़ पार करते समय आधी सडक़ को दाँयी ओर देखते हुए और शेष आधी सडक़ को बाँयी ओर देखते हुए पार करना चाहिए।उन्होंने आगे बतलाया कि दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चालक को सही लेन में चलना आना चाहिए। सडक़ में सबसे अन्तिम बायीं ओर की लेन का उपयोग भारी वाहन, धीमी गति के वाहन और बायीं ओर मुडने वाले वाहनों को करना चाहिए।

सड़कों की खराब स्थिति पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाईः साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज विभागीय मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर सड़कों एवं पुल-पुलियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तत्परता से तकनीकी स्वीकृति और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साव ने बैठक में कहा कि सभी मुख्य अभियंता कार्यालय कॉर्पोरेट दफ्तरों की तरह पूरी क्षमता और दक्षता से काम करें। उन्होंने विभाग की कार्य संस्कृति में बदलाव लाते हुए फील्ड से लेकर कार्यालय तक तेज गति और जवाबदेही से काम करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग करने और इनके खराब होने पर संबंधित ठेकेदारों से त्वरित मरम्मत कराने को कहा, ताकि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की स्थिति खराब पाए जाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसी सड़कों का तत्काल ठेकेदारों से मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के मुख्य अभियंता को भारत सरकार के साथ लगातार समन्वय कर स्वीकृतियों एवं कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने फील्ड पर निकलकर प्राथमिकता वाली सड़कों के कार्यों की प्रगति का हर सप्ताह निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नई सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए कलेक्टरों के साथ समन्वय कर भू-अर्जन की कार्यवाहियों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने के साथ ही सड़कों व पुलों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

उज्बेक अध्ययन दल ने लिया सुविधाओं का जायजा

रायपुर। भारत एवं उजबेकिस्तान के मध्य कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए उज्बेकिस्तान से आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार अधोसंरचनाओं, सुविधाओं तथा गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान अध्ययन दल ने इंदिरा गांधी कृषि विवि रायपुर की अनुसंधान प्रयोगशालाओं, कृषि अनुसंधान परियोजनाओं, स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन सुविधाओं तथा विवि की विभिन्न शैक्षणिक एवं नवाचार संरचनाओं का अवलोकन भी किया। इस प्रतिनिधिमंडल में बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उप-कुलपति प्रो. अब्रोर जोरायेव तुरोबोविच तथा समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसीन लाइवस्टॉक एवं बायोटेक्नोलॉजीस से अनुसंधान एवं नवाचार के उप-कुलपति प्रो. तयलाकोव तोलिब इसाकुलोविच सहित अन्य वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं वैज्ञानिक शामिल हैं। इस अवसर पर भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय शैक्षणिक, अनुसंधान एवं तकनीकी सहयोग सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया।

लखनपुर निज निवास पर मंत्री ने सुनीं क्षेत्रवासियों की समस्याएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज लखनपुर स्थित अपने निज निवास में क्षेत्रवासियों से आत्मीय भेंट की। इस दौरान आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और नागरिकों ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए मौके पर ही अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।

मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क निर्माण, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल संकट, राजस्व मामले और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ में आ रही दिक्कतों को साझा किया। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक नागरिक की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन पर निर्देशित करते हुए कहा कि जनसमस्याओं का समाधान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

संवाद के दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन और विकास को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव और शहर में बेहतर अधोसंरचना का निर्माण और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मंत्री ने अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देशित किया कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही अनिवार्य है। उन्होंने कहा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलने में देरी न हो। प्रशासनिक स्तर पर फाइलों को लंबित न रखा जाए। जनता का विश्वास ही सरकार की असली ताकत है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मई माह में हर घर में दुगुना बिल भेजा है सरकार ने :बैज

रायपुर। मई माह में लोगों का बिजली बिल दुगुना आया है, बढ़े बिजली बिल से जनता परेशान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार प्रायोजित लूट है बढ़े हुए बिजली बिल भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण छत्तीसगढ़ की जनता का महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। अप्रैल महीने की बिजली खपत का जो बिल लोगों के घरों में पहुंचा है उससे जनता परेशान हो गयी है। गर्मी के कारण 20 से 25

प्रतिशत तक बिजली खपत अधिक हुई होगी माना जा सकता है लेकिन जो बिल आम आदमी के घरों में पहुंचा है वह पिछले माह की अपेक्षा दुगुना है। सरकार बिजली के नाम पर जनता को लूट रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिजली के बढ़े बिल से पिछले 6 माह से जनता पर बोझ डाला जा रहा था लेकिन इस माह बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है। औसतन हर उपभोक्ता का बिजली बिल दुगुना आया है। बिजली बिल ज्यादा आने का तीन कारण है। सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिया है। बिजली बिल हाफ योजना बंद हो गई। स्मार्ट मीटर लगाए गए है जो अनाप शनाप खपत से अधिक रीडिंग बता रहा जिससे बिल अधिक आ रहा।

पूरे प्रदेश में भय का माहौल हैः शुक्ला

रायपुर। राजधानी में बम बनाये जाने का सामान मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि राजधानी के उरला क्षेत्र में एक घर से बड़ी मात्रा में बम बनाया जा रहा था। कल ही मेकाहारा के पास गैंगवार हो रहा था, घंटों सड़क पर चाकू, तलवार, फरसा लहराये जा रहे थे। गोली मारकर दो युवतियों की हत्या कर दी गयी। पुराने विधानसभा के पास व्यापारी से एक करोड़ की लूट हो गयी। सरकार और भाजपा कहती है कि सब ठीक है, प्रदेश और राजधानी की कानून

व्यवस्था नियंत्रण में है। सरकार बता दे कि अपराध का स्तर किस हद तक बढ़ेगा कि तब वह मानेगी की प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। राजधानी सहित प्रदेश में बढ़ी अपराध की घटनाएं सब्र बर्दाश्त के बाहर होते जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में बेलगाम हो चुके है, रोज हो रही लूट, चोरी, डकैती, चाकूबाजी, हत्याओं और आपराधिक घटनाओं से राजधानी में सहित पूरे प्रदेश में भय का माहौल है, रायपुर में लूट, हत्या और चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता भयावह हत्या की एक दो घटनाएं न होती हो, अपराधी इतने बेलगाम हो गये है कि सरेआम सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मार रहे, पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट : कानून व्यवस्था चिंतानीयः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर उजागर कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध दर 89.7 प्रति लाख आबादी है,

जबकि राष्ट्रीय औसत 76.3 प्रति लाख आबादी है। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। हत्या, लूट, मारपीट और ठगी जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समाज में बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहां वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार अपराध नियंत्रण के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग हैं। भाजपा सरकार में कानून नाम की चीज नहीं आपराधिक घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रति दिन 34 महिलाएं 20 बेटियां गायब हो रही है प्रतिदिन 8 से अधिक हत्या 9 से अधिक रेप की घटना हो रही है रोज दर्जनों चाकूबाजी हो रही है।

छात्र संघ को लेकर एनएसयूआई ने किया सीएम निवास का घेराव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार को ह्स्ड्ढ ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के नेतृत्व में प्रदेशभर से पहुंचे सैकड़ों छात्र-युवा कार्यकर्ताओं ने बूढ़ापारा से रैली निकालकर सीएम हाउस की ओर कूच किया। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शन के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई।

ह्स्ड्ढ कार्यकर्ताओं ने छात्र हित में चुनाव कराओ और लोकतंत्र बहाल करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश के सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी में तत्काल छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की गई। ह्स्ड्ढ का आरोप है कि पिछले कई साल से चुनाव नहीं कराए जा रहे, जिससे छात्रों की आवाज दब रही है। कार्यकर्ताओं ने छात्र हित में चुनाव कराओ और लोकतंत्र बहाल करो के नारे लगाए। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। कार्यक्रम में ह्स्ड्ढ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शामिल हुए। रायपुर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया।

कैट को मिला नया नेतृत्व परमानंद जैन बने प्रदेश अध्यक्ष

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन ने छत्तीसगढ़ में संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश नेतृत्व की नई टीम की घोषणा की है। राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुशंसा एवं प्रदेश कोर कमेटी की सर्वसम्मति से हुई बैठक में वरिष्ठ व्यापारी नेता परमानंद जैन को प्रदेश अध्यक्ष, युवा व्यापारी नेता अवनीत सिंह को प्रदेश महामंत्री तथा विजय पटेल को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेंद्र खटवानी को प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इस संबंध में कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डके सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के तत्कालीन चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, तत्कालीन अध्यक्ष परमानंद जैन, तत्कालीन महामंत्री सुरिंदर सिंह, तत्कालीन कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंथन, वासु माखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया।

महतारी वंदन योजना

महिला सशक्तिकरण की नई धारा

डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर

किसी भी राज्य की प्रगति का सशक्त आधार उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। जब महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त होती हैं, तब विकास की प्रक्रिया न केवल तीव्र होती है बल्कि समावेशी भी बनती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित 'महतारी वंदन योजना' इसी समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में स्थापित हो चुकी है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' के उस संकल्प को भी साकार कर रही है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई देती है।

महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। मार्च 2024 में प्रारंभ इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब तक 27 किस्तों में कुल 17,523 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह आंकड़ा केवल आर्थिक सहायता का प्रतीक नहीं, बल्कि राज्य सरकार की उस संवेदनशील सोच का परिचायक है, जो महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करती है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से सामने आ रही प्रेरक कहानियां इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि यदि सही दिशा और अवसर मिले, तो महिलाएं अपने जीवन की तस्वीर स्वयं बदल सकती हैं।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के ग्राम मझगंवा की श्रीमती हेमा सिंह इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने योजना से प्राप्त राशि को खर्च करने के बजाय बचत और निवेश का माध्यम बनाया। धीरे-धीरे उन्होंने एक छोटा किराना स्टोर प्रारंभ किया, जो आज उनके परिवार की आय का स्थायी स्रोत बन चुका है। उनकी यह यात्रा बताती है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।इसी प्रकार अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम रामनगर की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की श्रीमती करियो ने योजना की राशि से बकरी पालन प्रारंभ कर आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाया है। आज उनके पास कई बकरियां हैं और यह कार्य उनके परिवार की आजीविका का मजबूत आधार बन गया है।

नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा मावली हिल्स, वॉटर एडवेंचर भी शुरू

रायपुर। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य से भरपूर कांकेर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिले में भानुप्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुल्ला के पिच्चेकट्टा जलाशय को नए वॉटर एडवेंचर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सांसद भोजराज नाग ने यहां मावली हिल्स के नाम से विकसित किए गए नए वॉटर एडवेंचर का शुभारंभ किया। विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी भी इस दौरान उपस्थित थीं।

सांसद भोजराज नाग ने वाटर एडवेंचर का शुभारंभ करते हुए कहा कि कांकेर जिले में पिच्चेकट्टा जैसे सैकड़ों पिकनिक स्पॉट हैं। लेकिन पिछले कई दशकों तक माओवादी आतंक के चलते यहां के पर्यटन केंद्रों का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पहले बस्तर की पहचान गोला-बारूद से होती थी, अब यह पर्यटन केंद्र के तौर पर जाना जाएगा। नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दृढ़ इच्छाशक्ति से नक्सलवाद खत्म हो गया है।भानुप्रतापपुर की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने इस मौके पर कहा कि पिच्चेकट्टा जलाशय प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। सैलानियों की आवाजाही बढने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.